

**[SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY]**

packages. Training Division is indulging in indiscipline and demoralising the trainers' community as a whole. There are other irregularities in allocating training programmes. There is no policy of deployment of trainers in various parts of the country.

Therefore, I would request the Government to initiate measures to remove disparity in implementation of the trainers' development policy. The Government may immediately review the policy of trainers' development and take suitable action to implement training for all.

**HALF-AN-HOUR DISCUSSION**

**Points arising out of answer given on 7th May, 2012, to Starred Question No. 423 regarding 'Promotion of entrepreneurship and self-employment among minorities'**

**श्री मोहम्मद अदीब** (उत्तर प्रदेश) : सर, कल मेरे सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने एक डिटेल्ड खत मुझको भेजा और मैं उसको देखकर यह सोचने लगा कि इस पर कैसे रिएक्ट करूँ। मैं बार-बार यह कहता हूँ कि माझनौरटी मिनिस्ट्री सच्चर कमेटी का हवाला देती है कि सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर हमने माझनौरटी के लिए यह-यह किया है। सच्चर कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि इस देश में मुसलमानों की क्या दुर्दशा है, यह पता चल सके। सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि मुसलमान इस देश में दलितों के बराबर नीचे पहुँच गया है और उसके लिए कोई-न-कोई चाराहगो करना होगा। हमारी सरकार ने उसको कहा कि हम इम्पिलमेंट कर रहे हैं और इसके लिए एक माझनौरटी मिनिस्ट्री बनाई है। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे।

कांग्रेस पार्टी ने माझनौरटी मिनिस्ट्री बनाने के बाद कहा कि हम 15 सूत्री कार्यक्रम ला रहे हैं जिसमें मुसलमानों को including other minorities, बहुत फायदे होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि चूंकि माझनौरटीज में, मुस्लिम माझनौरटी सब से पीछे है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हें दिया जाएगा, लेकिन इस खत के आने के बाद और दसियों खुतूत और information के बाद, जो मैंने और मेरे साथियों ने collect की है, उससे यह पता चलता है कि मुसलमान को कुछ भी नहीं मिला है। सर, मुसलमानों को bifurcation के लिए हमेशा कहा गया कि आप कुछ दीजिए। मुझे मंत्री महोदय के पत्र में सबसे बेहतर चीज यह लगी और उसमें यह कहा गया कि, हमने मैट्रिक, प्रिमैट्रिक और पोर्ट-मैट्रिक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी हैं। इसमें यह क्लेम किया गया है कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों को हमने स्कॉलरशिप दी हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह फिर कैसे बन गयी? जब आप example के तौर पर एक तीसरे दर्जे के बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं, वह पास कर के चौथे दर्जे में भी जाता है और वही बच्चा पांचवे दर्जे में भी जाता है, तो इन तीन सालों की फिर को जोड़कर, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि 1 करोड़ 40 लाख की जो फिर आपने दी है, वह सिर्फ उन बच्चों की है जिन्हें मिलाकर आप हर साल स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उन्हें club करके आपने दी है या 1 करोड़ 40 लाख अलग बच्चों को स्कॉलरशिप दी है? यही एक स्कीम है और इसमें आपने लिखा भी है कि 70 परसेंट मुसलमानों को दी गयी है। यह ठीक बात है और 70 परसेंट उनका शेयर बनता है। यह बिल्कुल acceptable है। फिर यह कहा गया कि हम और स्कीम लाए हैं जिसके लिए हमने 90 जिले तय किए हैं और इनमें 3,780 करोड़ रुपए डबलमेंट के लिए दिए हैं। आपने माझनौरटी के लिए बहुत बड़ा खजाना खोल दिया! जहां लाखों-लाख का बजट हो, आपने कहा कि हमने 3,780 करोड़ रुपए दे दिए हैं और उसमें से भी 840 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। यह हमारी हैसियत है। यह कहा गया कि ये वे जिले

हैं जहां concentrated muslim population है। उसके बाद कहा गया कि हमने 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बहुत-सी योजनाएं दी हैं। आपने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेवलपमेंट को दी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को दी हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दी हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमको मिला क्या है? मैं बराबर यह पूछ रहा हूं कि आप हमको क्या दे रहे हैं। यह कहा गया कि हमने इतनी स्कीम्स sanctioned कर दी हैं और बहुत-सी योजनाएं पर कहा गया है कि इन पर विचार हो रहा है। मैं दिल्ली स्टेट के माइनोरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जेन कम्युनिटी को भी माइनोरिटी में शामिल किया गया है। वे 2 परसेंट हैं, लेकिन उन्हें 50 परसेंट की फाइनेंशियल एड दी गयी है। मैं यह पार्लियामेंट में बोल रहा हूं और इसकी सनद मेरे पास है। सरदार 5 परसेंट हैं, उन्हें 17 परसेंट की फाइनेंशियल एड दी गयी है, वहीं 70 परसेंट मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें एक परसेंट की फाइनेंशियल एड दी गयी है। हमेशा यह पूछा गया है कि आप bifurcate कर के बताइए कि आप हमें क्या देना चाहते हैं और हमेशा यह कहा गया कि हम डाटा कलैक्ट कर रहे हैं। अरे साहब, कहीं कोई बम ब्लास्ट होता है और कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो पूरे मुसलमानों के खानदान के डाटा आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको यह डाटा नहीं मिल रहा है कि कितने मुसलमानों को मकान दिए हैं? यह आपको नहीं मालूम कि कितने बच्चों को आपने दूसरी योजनाओं में भला किया है? आप जितनी योजनाएं बना रहे हैं...

उन योजनाओं का हाल यह कर रखा है कि आप कहते हैं कि हमने लैंडिंग की है, बैंकों को लोन दिया है। यदि बैंकों को लोन दिया है, तो आप उनके नाम, पते दे सकते हैं कि उनको आपने कितना दिया है? इस मूल्क में एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी सिर्फ मुसलमान हैं या न्यूयोर्क-बुद्धिस्ट हैं। इस मूल्क में पारसी एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, इस मूल्क में सरदार एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। अगर माइनोरिटी का रोल ला रहे हैं, तो माइनोरिटी का रोल तो आप जरूर ले आइए। आपने यह कहा, एक मिसाल के तौर पर, आपने बजट का भी एलोकेशन किया है। मैं समझता हूं कि जब बजट रिव्यू होता है, तो बढ़ा के दिया जाता है, मगर यहां लिखा है कि 2011-12 में हमारा रिवाइज बजट, यानी जो बजट एस्टीमेट था वह 2750 का, वह 2002 का रिवाइज किया गया, यानी रिवाइज बजट कम हो गया। यहां प्रणब मुखर्जी साहब अपना बजट लाते हैं, रेलवे मंत्री भी लाते हैं, जो कि हमेशा बढ़ा कर लाते हैं और कहते हैं कि इस बजट को और बढ़ाइए, लेकिन हमें जो डिस्ट्रिब्यूशन मिला उसको भी कम किया गया।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Now, please conclude. Put your questions.

**श्री मोहम्मद अदीब :** सर, यह इतनी मोटी किताब है।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** क्या करें? यह तो आज हाफ एन आवर डिस्कशन है।

**श्री मोहम्मद अदीब :** सर, आपने मुझे टाइम दिया है, तो यह हकाईक तो मैं बयान कर दूं।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** अदीब साहब, यह हाफ एन आवर डिस्कशन है। ... (व्यवधान)...

**श्री मोहम्मद अदीब :** सर, हाफ एन आवर डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूं। आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सवालात हाउस में किए गए हैं और जो उसके जवाब दिए गए हैं, वे तो पढ़ कर सुना देने दीजिए। देखिए, एक सवाल के जवाब में बताया गया, हमारी बहुत सीनियर लीडर मोहसिना किदर्वई साहिबा हैं....

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** This is not a speech. अदीब साहब, आपने आठ मिनट ले लिए। You put your questions. This is Half-an-Hour Discussion.

**श्री मोहम्मद अदीब :** सर, इस हाउस में परसों यह जवाब दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है, जो जवाब दिया है मिनिस्ट्री ने, यह कहा गया है कि details of funds sanctioned and unutilised. यहां

[**श्री मोहम्मद अदीब**]

इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 परसेंट युटिलाइज नहीं हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश का यह लिखा है। बिहार का सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 24,888 लाख रुपए सेवकशन हुए, 12,044 ही खर्च हुए और 13,000 नहीं बंटे। यह उन पैसों की दुर्दशा है, जिसके ऊपर हमें कहा जाता है सेवकशन ऑफ मनी, माइनोरिटीज को एलोकेट होती है। यह भी कहा जाता है कि हम माइनोरिटीज के बहुत ही सपोर्टर हैं और माइनोरिटीज की हम बड़ी फिक्र कर रहे हैं। जरा सोचिए, हमने तो आप पर विश्वास किया और हमारे साथ ऐसा बड़ा सितम हुआ। बंगाल के अंदर 40 परसेंट, यानी डबल जीरो, वहां काम ही नहीं हुआ। माइनोरिटीज को अगर आप माइनोरिटीज की हैसियत से भी मानते हैं, मेरा मेन ऑब्जेक्शन यह है कि माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को अगर आप माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कहते हैं, देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी हो कह दीजिए, लेकिन ऐसा मत कहिए कि चूंकि सच्चर कमेटी ने कहा था इसलिए हम करेंगे।

सर, जिस दिल्ली में हम रहते हैं, यहां एक बस्ती ओखला है, जिसमें पांच लाख मुसलमान रहते हैं। यहां सरकार का एक स्कूल नहीं है, एक अस्पताल नहीं है। बीच में एक सड़क है, दूसरी तरफ न्यू फ्रेड्स कालोनी है, जो हिंदुस्तान की बेहतरीन कालोनियों में से पाई जाती है। हमको आपने यह दिया है। इसी दिल्ली में सीलमपुर के इलाके में एक अस्पताल नहीं है। सिब्बल साहब की मिनिस्ट्री से यह कहा गया था कि वहां हम सरकारी स्कूल खोल रहे हैं। दिल्ली में नहीं खोला, तो आप और कहां खोलेंगे?

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** अदीब साहब, This is not a discussion on that. This is a question on entrepreneurship and self-employment. You stick to the question.

**श्री मोहम्मद अदीब :** मैं सिर्फ दो बातें वाजेह कर देना चाहता हूँ। एक तो यह कि एक करोड़ चालीस लाख जो स्कॉलरशिप दी है, यह बता दें कि यह एक करोड़ चालीस लाख अलग लोगों को दिए गए हैं या वही लोग जो आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें एड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं?

दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको आगे चलाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माइनोरिटी मिनिस्ट्री की कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। आज कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, जिसकी स्टैंडिंग कमेटी न हो, लेकिन इन मिनिस्ट्री की कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। अगर इसको सही तरीके से channelize करना है, अगर सही तरीके से माइनोरिटी को फलाहोबहबूद करना है, तो आपको इसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक स्टैंडिंग कमेटी बनानी पड़ेगी और जब भी आप पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर जवाब दें, तो bifurcate करके दें कि किस कम्युनिटी को आप कितना दे रहे हैं और किस शोबे में कितना दे रहे हैं और जो आपने लिखा है कि हमने 13 मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी है कि वे 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत काम करें, तो उन 13 मंत्रालयों को भी यह बताना पड़ेगा कि वे किस कम्युनिटी को कितना दे रहे हैं? अगर यह नहीं करते हैं, तो यह ... (व्यवधान)...

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** All this does not come under this question. What is this?

**श्री मोहम्मद अदीब :** आप बोलने ही नहीं देते हैं ... (व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** 12 मिनट हो गए हैं ... (व्यवधान)...

**श्री मोहम्मद अदीब :** आप बोलने ही नहीं देते हैं ... (व्यवधान)...

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** It is a Half-an-Hour Discussion. You have given notice for Half-an-Hour Discussion. You could have given notice for Short Duration Discussion. उसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे।

**شی مہممد ادیب :** سر، جب Short Duration کا نوٹس دیا جاتا ہے، تو ہمارے دیتھل میں بات ہوتی ہے۔ مंत्रالय نے اک رات پہلے مुझے یہ document بےجا، آپکے یہاں ہمارے کارنامہ کرننا بھی مुशکل ہے۔ یہ بڑی مुशکل کی بات ہے۔ بار-بار کیسے جاکر کہو، کیسے فریاد کرو؟

**उपसभाध्यक्ष (پرو. پی. جے. کوریان) :** آپ نوٹس دے دیجیاں... (વ्यवधान)...

**شی مہممد ادیب :** یہ ہلکشان کا وکٹ ٹھوڈے ہی ہے، یہ پارلیامنٹ ہے... (વ्यवधान)...

† [جناب محمد ادیب (ائز پردویش) : سر، کل میرے سوال کے جواب میں مانع

منتری جی نے ایک ڈبلہ خط مجھے کو بھیجا ہے اور میں اس کو دیکھہ کر وہ سوچنے لگا کہ اس پر کیسے ریکٹ کروں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مانزارٹی سچر کمیٹی کا حوالہ دیتی ہے کہ سچر کمیٹی کی ریکمینڈیشن کے اوپر ہم نے مانزارٹی کے لئے یہ کیا ہے۔ سچر کمیٹی اس لئے بنائی گئی تھی کہ اس دیش میں مسلمانوں کی کیا دردشا ہے؟ سچر کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ مسلمان اس دیش میں دلتوں کے برابر، نیچے پہنچ گیا ہے اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی چارہ گو کرنا ہوگا۔ ہماری سرکار نے اس کو کہا کہ ہم امپلی مینٹ کر رہے ہیں اور اس کے لئے ایک مانزارٹی منسٹری بنائی ہے۔ اس کے لئے ہم کانگریس پارٹی کے بیشہ شکرگزار رہیں گے۔ کانگریس پارٹی نے مانزارٹی منسٹری بنائے کے بعد کہا کہ ہم 15 نکاتی پروگرام لا رہے ہیں، جس میں مسلمانوں کو including other minorities، مانزارٹیز میں، مسلم مانزارٹی سب سے پچھے ہے، اس لئے اس میں سب سے زیادہ حصہ انہیں دیا جائے، لیکن اس خط کے ائے کے بعد اور دسیوں خطوط اور انفارمیشن کے بعد، جو میں نے اور میرے ساتھیوں نے کلکٹ کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ سر، مسلمانوں کو bifurcation کے لئے بیشہ کہا گیا کہ اپ کچھ دیجئے۔ مجھے منتری مہودے کے خط میں سب سے پہنچ چیز ہے لگی اور اس میں یہ کہا گیا کہ، ہم نے میٹرک، پری-میٹرک اور پوسٹ میٹرک کے بچوں کو اسکالر شپ دی ہیں۔

† Transliteration in Urdu Script.

[جناب محمد ادیب]

اُن میں سے claim کیا گیا ہے کہ 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے اسکالر شپ دی ہیں، لیکن میری سمجھتے ہیں نہیں اُرہا ہے کہ یہ فیگر کہسے بن گئی؟ جب اُب example کے طور پر ایک تیسرے درجے کے بھرے کو اسکالر شپ دیتے ہیں، وہ پاس کر کے جو تھے درجے میں بھی جلتا ہے اور وہی بھرے پانچوں درجے میں بھی جلتا ہے، تو اُن نین سالوں کی فیگر کو خوڑ کر، میں اُب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 1 کروڑ 40 لاکھ کی جو فیگر اُب نے دی ہے، اُبھیں club کر کے اُب نے دی ہے با 1 کروڑ 40 لاکھ الگ بچوں کو اسکالر شپ دی ہے؟ بھی اُبک اسکیم ہے اور اُن میں اُب نے لکھا ہے کہ 70 فیصد مسلمتوں کو دی گئی ہے۔ یہ ثابت ہاتھ ہے اور 70 فیصد ان کا شینر بتتا ہے۔ یہ بالکل acceptable ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہم اور اسکیم لائے ہیں جس کے لئے ہم نے 90 ضلع طے کئے ہیں اور ان میں 3،780 کروڑ روپیے ٹیولپیٹ کے لئے دے رہے ہیں۔ اُب نے ملقارثی کے لئے بہت بڑا خزانہ کھیول دیدا جہاں لاکھوں لاکھ کا بجٹ ہو، اُب نے کہا کہ ہم نے 3،780 کروڑ روپیے دے دئے ہیں اور اُن میں سے بھی 840 کروڑ روپیے خرچ نہیں ہونے ہیں۔ یہ بماری حیثیت ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ وہ ضلع ہیں جہاں concentrated Muslim population ہے۔ اُن کے بعد کہا گیا کہ ہم نے 15 نکاتی پروگرام کے تحت بہت سی یونیورسٹیز دی ہیں۔ اُب نے کہا کہ منشیٰ اف رورڈ ٹیولپیٹ منشیٰ کو دی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کو

ملا کیا ہے؟ میں برابر یہ پوچھہ رہا ہوں کہ اپ ہم کو کہا دے رہیں ہیں؟ یہ کہا گیا کہ ہم نے انکی اسکیس sanctioned کر دی ہیں اور بہت سی جگہوں پر کہا گیا ہے کہ اس پر وچار ہو رہا ہے۔ میں دبلي اسٹیٹ کے ماننارٹی فائنسیشنل کارپوریشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دبلي میں جن کمیونٹی کو بھی ماننارٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ 2 فیصد ہیں، لیکن انہیں 50 فیصد کی فائنسیشنل ایڈ دی گئی ہے۔ میں یہ پارلیمنٹ میں بول رہا ہوں اور اس کی سند میرے پاس ہے۔ سردار 5 فیصد، انہیں 17 فیصد کی فائنسیشنل ایڈ دی گئی ہے۔ وہیں 70 فیصد مسلمان ہیں، لیکن انہیں 1 فیصد کی فائنسیشنل ایڈ دی گئی ہے۔ یہیشہ یہ پوچھا گیا کہ اپ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں اور یہیشہ یہ کہا گیا کہ ہم ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ارے صاحب، کبھیں کونی ہم بلاست ہوتا ہے اور کبھیں کونی اتنک-وادی پکڑا جاتا ہے، تو پورے مسلمانوں کے خاندان کے ڈاٹا اپ کو مل جاتے ہیں، لیکن اپ کو یہ ڈاٹا نہیں مل رہا کہ کتنے مسلمانوں کو مکان نہیں ہے؟ یہ اپ کو نہیں معلوم کہ کتنے بھوں کا اپ نے دوسری یو جناوں میں بھلا کیا ہے؟ اپ جتنی یو جناویں بتا رہے ہیں۔ ان یو جناوں کا حال یہ کہ رکھا ہے کہ اپ کہتے ہیں کہ ہم نے لینڈنگ کی ہے، بننکوں کو لوں دیا ہے۔ اگر بننکوں کو لوں دیا ہے۔ اگر بننکوں کو لوں دیا ہے، تو اپ ان کے نام، پتے دے سکتے ہیں کہ ان کو اپ نے کتنا دیا ہے؟ اس ملک میں ایجوکیشنل بیک-ورڈ کمیونٹی صرف مسلمان ہیں یا نیویو بذہشت ہیں۔ اس ملک میں پارسی ایجوکیشنل بیک-ورڈ نہیں ہے، اس ملک میں سردار

[جناب محمد ادیب]

ایجوکیشنلی بیک-ورڈ نہیں ہے۔ اگر مالٹارشی کا رول لا رہے ہیں، تو مالٹارشی کا رول تو آپ ضرور لے آئیے۔ آپ نے یہ کہا، ایک مثال کے طور پر، آپ نے بحث کا بھی ایلوکیشن کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بحث روپیو ہوتا ہے، تو بڑھا کے دیا جاتا ہے، مگر یہاں لکھا ہے کہ 12-2011 میں ہمارا روائز بحث، یعنی جو بحث ایسٹیمیٹ تھا وہ 2750 کا، وہ 2002 کا روائز کیا گیا، یعنی روائز بحث کم ہو گیا۔ یہاں پرنٹ مکھرجی صاحب اپنا بحث لاتے ہیں، ریلوے منٹری بھی لاتے ہیں، جو کہ پیشہ بڑھا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بحث کو اور بڑھانیے، لیکن میں جو ڈسٹریبوشن ملا، اس کو بھی کم کیا گیا۔]

THE VICE-CHAIRMAN (RPOF. P.J. KURIEN) : Now, please conclude. Put your questions.

‡ [جناب محمد ادیب] : سر، یہ اتنی موٹی کتاب ہے۔

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی جے۔ کورنین) : کیا کریں؟ یہ تو آپ اج 'باف این اور' ٹسکشن ہے۔

جناب محمد ادیب : سر، آپ نے مجھے ثانی دیا ہے، تو یہ حقالق تو میں بیان کر دوں۔

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی جے۔ کورنین) : ادیب صاحب، یہ 'باف این اور' ٹسکشن ہے۔ (مدخلت) ...

---

† Transliteration in Urdu Script.

جناب محمد ادیب : سر، 'باف این اور' ٹسکشن ہے، لیکن میں آپ کو صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو سوالات باوس میں کئے گئے ہیں اور جو اس کے جواب دئے گئے ہیں، وہ تو پڑھہ کر سنا دینے دیجئے۔ دیکھئے، ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا، بماری بہت سینفر لیڈر محسنہ قدوامی صاحبہ ہیں،۔۔۔

THE VICE-CHAIRMAN (RPOF. P.J. KURIEN) : This is not a speech. آپ نے اٹھہ منٹ لے لئے۔ You put your questions. This is Half-an-Hour Discussion.

آج[جناب محمد ادیب : سر، اس باوس میں پرسوں یہ جواب دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے، جو جواب دیا ہے منسٹری نے، یہ کہا گیا ہے کہ [بہار انہوں نے details of funds sanctioned and unutilized. کیا کہ ان پر دیش میں 50 فیصد utilize نہیں بوا۔ دیکھئے، ان پر دیش کا یہ لکھا ہے۔ بہار کا سن لیجئے، انہوں نے کہا ہے کہ ان پر دیش میں 24,888 لاکھ روپے sanction ہونے، 12,044 ہی خرچ ہونے اور 13,000 نہیں بنٹے۔ یہ ان پیسوں کی دردشا ہے، جس کے اوپر ہمیں کہا جاتا ہے سلیکشن آف منی، ماننارٹیز کو ایکوکیٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ماننارٹیز کے بہت بی سپورٹر ہیں اور ماننارٹیز کی ہم بڑی فکر کر رہے ہیں۔ ذرا سوجھئے، ہم نے آپ پر وشوں کیا اور بھارتے

---

† Transliteration in Urdu Script.

[جناب محمد ادیب]

ساتھے ایسا بڑا ستم بوا۔ بنگال کے اندر 40 فیصد، یعنی ڈبل زیرو، وہاں کام ہی نہیں بوا۔ ماننارٹیز کو اگر آپ ماننارٹیز کی حیثیت سے بھی مانتے ہیں، میرا میں آجیکشن ہے کہ ماننارٹی افیئرنس منسٹری کو اگر آپ ماننارٹی افیئرنس منسٹری کہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہو کہہ دیجئے، لیکن ایسا مت کہتے ہیں کہ چونکہ سجر کھٹکی نے کہا تھا اس لئے ہم کریں گے۔

سر، جس دبلي میں ہم رہتے ہیں، وہاں ایک بستی اوکھلا ہے، جس میں پانچ لاکھ مسلمان رہتے ہیں۔ وہاں سرکار کا ایک اسکول نہیں ہے، ایک اسپتال نہیں ہے، بیچ میں ایک سڑک ہے، دوسری طرف نیو-فرینچس

کالونی ہے، جو ہندوستان کی بہترین کالونیوں میں سے پانی جاتی ہے۔ ہم کو آپ نے یہ دیا ہے۔ اسی دبلي کے سیلم پور کے علاقے میں ایک اسپتال نہیں ہے۔ سبیل صاحب کی منسٹری سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں ہم سرکاری اسکول کھول رہے ہیں۔ دبلي میں نہیں کھولا، تو آپ اور کہاں کھولیں گے؟

آپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی جے۔ کورنین) : ادیب صاحب، [

This is not a discussion on that. This is a question on entrepreneurship and self-employment. You stick to the question.

﴿جناب محمد ادیب : میں صرف دو باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک کروڑ چالیس لاکھہ جو اسکالر شپ دی ہے، یہ بتا دیں کہ یہ اپنے کروڑ چالیس لاکھہ الگ لوگوں کو دئے گئے ہیں یا وہی لوگ جو اگئے پڑھنے جلے چاریے ہیں، اس میں ایڈ کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں؟﴾  
 دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اگئے چلانا چاہئے ہیں، تو میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ مانمارشی منسٹری کی کوئی استینڈنگ کمیٹی نہیں ہے۔ اج کوئی ایسی منسٹری نہیں ہے، جس کی استینڈنگ کمیٹی نہ ہو، لیکن اس منسٹری کی کوئی استینڈنگ کمیٹی نہیں ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے چینلاز کرنا ہے، اگر صحیح طریقے سے مانمارشی کو فلاخ و بیبود کرنا ہے، تو آپ کو اس کے لئے ایک سسٹم بنانا پڑے گا، ایک استینڈنگ کمیٹی بنانی پڑے گی اور جب بھی آپ پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر جواب دیں، تو bifurcate کر کرے دیں کہ کس کمیوتی کو آپ کتنا دے رہے ہیں اور کس شعبے میں کتنا دے رہے ہیں اور جو آپ نے لکھا ہے کہ یہ نے 13 منڑالیوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ 15 نکاتی پروگرام کرے تھت کام کریں، تو ان 13 منڑالیوں کو بھی یہ بنانا پڑے گا کہ وہ کس کمیوتی کو کتنا دے رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ... (مدخلت) - [

THE VICE-CHAIRMAN (RPOF. P.J. KURIEN) : All this does not come under this question. What is this?

﴿جناب محمد ادیب : آپ بولئے بھی نہیں دیتے ہیں ... (مدخلت) -

---

† Transliteration in Urdu Script.

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی جے کورنین) : 12 منٹ ہو گئے ہیں  
۔۔۔ (مداخلت) ۔۔۔

جناب محمد ادیب : اپ بولئے ہیں نہیں دیتے ہیں ۔۔۔ (مداخلت) ۔۔۔

THE VICE-CHAIRMAN (RPOF. P.J. KURIEN) : It is a Half-an-Hour Discussion. You have given notice for Half-an-Hour Discussion. You could have given notice for Short Duration

۔۔۔ [اس میں اپ کو 3 گھنٹے ملیں گے] Discussion.

جناب محمد ادیب : سر، جب Short Duration کا نوٹس دیا جاتا ہے،

تو اس میں ڈیل میں بات بوتی ہے۔ منڑالیہ نے ایک رات پہلے مجھے ہے ڈاکیومنٹ بھیجا، اپ کے بہان اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ بری مشکل کی بات ہے۔ بار-بار کس سے جاکر کہیں، کس سے فریاد کریں؟

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی جے کورنین) : اپ نوش دے دیجئے  
۔۔۔ (مداخلت) ۔۔۔

جناب محمد ادیب : یہ الیکشن کا وقت تھوڑے بھی بے، یہ پارلیمنٹ بے  
۔۔۔ (مداخلت) ۔۔۔

[ختم شد)

---

† Transliteration in Urdu Script.

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Hon. Members, it is a Half-an-Hour Discussion. It is a clarification on a particular question. You are requested to put only questions. I have nine names with me. Each Member can take two minutes. So, just put questions. Naqvi ji, just put questions. If you want a discussion on the Ministry of Minority Affairs, there are other ways. You can give notice. This is not an occasion for that.

**श्री मुख्तार अब्बास नक्वी (उत्तर प्रदेश) :** उपसभाध्यक्ष जी, यह चर्चा और यह Half-an-Hour Discussion किन कारणों से हुआ है? जिस दिन माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर जवाब दे रहे थे, उस समय यह चर्चा हुई कि उनेक लिए क्या बजट है और उस बजट का कितना उपयोग इस मंत्रालय ने किया है? उस समय माननीय मंत्री जी कुछ जवाब नहीं दे पाए थे। तब सदन में यह राय बनी थी कि इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, ऐसी चर्चा 14 मार्च, 2011 को भी हुई थी, जिसमें अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय के बारे में, उसके कामकाज के बारे में और उसमें अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में चर्चा हुई थी और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था। 14 मार्च, 2011 से अब 2012 आ गया, लेकिन इस एक वर्ष के दौरान गाड़ी वर्ही की वर्ही है। विकास की गाड़ी उस समय रेंग रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय यह रुक गई है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात एक शेर के रूप में कहना चाहता हूं-

“हर बार हमको घाटा हुआ तेरे साथ में,  
मिट्टी खरीदनी पड़ी सोने के भाव में।

तन ढक लिया कभी, तो कभी पेट भर लिया,  
मारा गया गरीब इसी रख-रखाव में।

अब तू बुलंदियों से मुझे गालियां भी दे,  
यह चूक तो हमीं से हुई हैं चुनाव में।”

आप अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करने के आपके बड़े-बड़े वायदे और इरादे हैं, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। बाद में वह आरक्षण की अफीम निकलती है और वह आरक्षण की ऐसी अफीम है, जो expired है। लगता है कि वह अंग्रेजी अफीम थी। एक कहावत है-

“तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है,  
ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है।”

तो वह दवा इनको रिएक्ट कर गई, वह आरक्षण की अफीम इनको रिएक्ट कर गई और इनको उसका कोई लाभ नहीं मिला। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि आज अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तीकरण और उससे जुड़े हुए सवाल बार-बार उठाए जाते हैं।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** नक्वी जी, एक मिनट...इस Question का scope सिर्फ इतना है - ‘Promotion of entrepreneurship and self-employment among minorities’ - इसके बारे में आपको question पूछना है, तो पूछिए, वरना मैं allow नहीं करूँगा। This is not a discussion on the Ministry of Minority Affairs ... (Interruptions)... You see the rules. This is Half-an-

[प्रो. पी.जे. कुरियन]

Hour Discussion, and the scope of the discussion is only that particular question, that is, Question No. 423 raised on 7th May ...(*Interruptions*)...

**SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI :** on a point of order. सर, आप उस Question को मंगा लीजिए। उस Question का विषय था कि अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास में इस मंत्रालय का बजट क्या है और उसका क्या हुआ?

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** You have taken three minutes, and now, you put your questions ...(*Interruptions*)...

**श्री मुख्तार अब्बास नक्वी :** सर, हम उस पर नहीं बोलेंगे, तो किस पर बोलेंगे? आप बताइए। All the issues are related to that question.

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** You put your questions, if you want. It cannot be a lecture.

**श्री मुख्तार अब्बास नक्वी :** इसलिए मेरा यह कहना है ...(*व्यवधान*)...

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Now, please conclude.

**श्री मुख्तार अब्बास नक्वी :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है ...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** कहना नहीं, आपको पूछना है।

**श्री मुख्तार अब्बास नक्वी :** मैं पूछ रहा हूं। महोदय, माननीय मंत्री जी के पास कई मंत्रालय हैं। माननीय मंत्री जी की इच्छा ईमानदारी से इस मंत्रालय में काम करने की ओर इस मंत्रालय के कार्यों को आगे बढ़ाने की हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वे बोझ से काफी दबे हों और यह जो अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय है, वह अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय ad-hoc मिनिस्ट्री है। यह वर्ष 2006 में बना और उस मंत्रालय के कार्यालय को बनने में छः महीने लगे और आज भी यह मंत्रालय अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए nodal मिनिस्ट्री है। तो वह मंत्रालय उसकी देखरेख कर रहा है या केवल दूर से देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा है? महोदय, यह मुद्दा बहुत बड़ा है और मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन पिछले आठ सालों में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार ने कितना बजट अब तक रखा और उस बजट में से कितना खर्च हुआ? ...(*समय की घंटी*)... हमारी जानकारी में 87 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए उस बजट में हैं और उन 87 रुपयों में से 7 रुपए भी अल्पसंख्यकों के विकास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ...(*समय की घंटी*)... यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इन मुद्दों पर, जो मुद्दे ...(*व्यवधान*)... ...(*समय की घंटी*)... अभी अदीब साहब ने इन तमाम सवालों को कहा, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं ...(*समय की घंटी*)...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** अली अनवर अंसारी जी, बोलिए। ...(*व्यवधान*)...

**श्री मुख्तार अब्बास नक्वी :** सर, आप ...(*व्यवधान*)...

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** You have taken five minutes ...(*Interruptions*)... I have ten names with me. If everybody takes ten minutes, then, how much time will be required? ...(*Interruptions*)...

**श्री मुख्तार अब्बास नक्वी :** सर, कम से कम पांच-छः मिनट तो बोलने का मौका दीजिए। ... (व्यवधान)...

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** You look at the Board. You have taken five minutes ... (*Interruptions*)... देखिए, बोर्ड को देखिए। ... (व्यवधान) ... अली अनवर अंसारी जी, आप बोलिए। ... (व्यवधान)...

**श्री मुख्तार अब्बास नक्वी :** सर, एक last point बोलने दीजिए।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Other things you write to the Minister. I will not allow ... (*Interruptions*)... There should be some rule. I have ten names ... (*Interruptions*)... Naqvi ji, this is indiscipline ... (*Interruptions*)...

**श्री मुख्तार अब्बास नक्वी :** सर, यह आपको भी पसंद आएगा। यह हिन्दी में है, आप सुन लीजिए—

“तू दरिया में तूफान क्या देखता है,  
खुदा है, निगेहबान क्या देखता है,  
तू हाकिम बना है, तो इंसाफ भी कर,  
तू हिन्दू-मुसलमान क्या देखता है?”

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** अब ठीक है, धन्यवाद। अंसारी जी, आप दो मिनट में सिर्फ question पूछिएगा।

**श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही सलमान खुर्शीद साहब की चिट्ठी मिली, जो आंकड़ों का दस्तावेज़ है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी की जब बात आती है...

जहाँ माझनौरिटी की बात आती है, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात आती है, सच्चर कमेटी ने कहा है कि सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है, उनका रीप्रेजेंटेशन है, वह दो से तीन परसेंट के बीच में है। हम जानना चाहते हैं कि उसको enhance करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है, आपकी क्या उपलब्धि है? महोदय, सच्चर कमेटी ने Equal Opportunity Commission बनाने की मांग की है। उसके बारे में आपने क्या किया है? दूसरा, आप आंकड़े दे रहे हैं कि इतने लोगों को वजीफा दिया, इतने लोग बैंक के लोन के beneficiaries हैं। सर, यह इतनी बड़ी marathon exercise है, चार सौ पेज की रिपोर्ट है, और इस कमेटी का नाम है, Prime Minister's High Power Committee. इस High Power Committee ने अगर कुछ लोगों का वजीफा ही बढ़ाना था, अगर कुछ लोगों को लोन ही देना था - पहले सौ को देते थे, अब दो सौ को दे दिया - तो इसके लिए इस High Power Committee को बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा तो आप executive order से कर सकते थे। सवाल यह है कि आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए हैं, फराहम कराए हैं? महोदय, जो लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते थे, मुख्तार अब्बास नक्वी साहब से भी हम कहते हैं कि आप शेर-ओ-शायरी तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चर कमेटी ने उस मुस्लिम तुष्टिकरण की बात को खारिज किया है। इसके लिए सबसे ज्यादा शर्मिदगी इस पक्ष में होनी चाहिए, जो 45 साल तक हुक्मत में रहे हैं। आज हालत क्या है? मैं उन लोगों में नहीं हूं जो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं और उन लोगों में भी नहीं हूं जो आरक्षण की बात सुनकर भड़क जाते हैं। क्यों नहीं एक जम्प दिया जाए? हम सब मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात नहीं कर रहे।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Please conclude.

**श्री अली अनवर अंसारी :** सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों में भी दलित हैं, ईसाइयों में भी दलित हैं। यह सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ईसाइयों की भी बात है। उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** चार मिनट हो गए हैं, अब कनकलूड कीजिए।

**श्री अली अनवर अंसारी :** सर, आपने इतना बड़ा सवाल छेड़ दिया है और अब आप कह रहे हैं कि मैं दो मिनट में समाप्त करूँ।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** मैं क्या करूँ? चार मिनट हो गए हैं।

**श्री अली अनवर अंसारी :** सर, जितना टाइम आपने इन लोगों को दिया है, कम से कम उतना टाइम तो हमें भी दीजिए। कृपया हमारे साथ नाइंसाफी मत कीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** उनको पांच मिनट दिए हैं। ...**(व्यवधान)**...

**श्री अली अनवर अंसारी :** हम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, इधर से भी कह रहे हैं, उधर से भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के मामले में, धारा 341 के मामले में जो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, 1950 के presidential order के ज़रिए धारा 341 पर जो religious ban लगा दिया है, हम उस धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ईसाइयों भी कर रहे हैं। सच्चर कमेटी ने सिफारिश की है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की है। ...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** प्लीज़, कनकलूड करिए।

**श्री अली अनवर अंसारी :** महोदय, कृपया मुझे सुन लिया जाए। बिहार विधान सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा है। ...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** अंसारी जी, यह क्वेश्चन पूछने का अवसर है, स्पीच करने का अवसर नहीं है।

**श्री अली अनवर अंसारी :** बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भी भेजा है, आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा ने भी भेजा है।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** This is indiscipline. आप क्वेश्चन पूछिए।

**श्री अली अनवर अंसारी :** श्री राजशेखर रेड्डी साहब ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मरने से 15 दिन पहले प्रस्ताव पास करके भेजा। वे तो सलमान साहब की पार्टी के थे। हम कहना चाहते हैं कि इस सवाल पर एक नेशनल कंसेंसस बना है। सलमान खुर्शीद साहब, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं। आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। ...**(व्यवधान)**... सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** अंसारी जी, आप क्वेश्चन पूछिए।

**श्री अली अनवर अंसारी :** वही पूछ रहा हूँ। आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, माइनरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी ने जो कहा है कि दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों के साथ मज़हब के आधार पर भेदभाव हो रहा है, वह unconstitutional है, आप सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?

आप as a Law Minister क्यों नहीं दे रहे हैं? भारत सरकार का अटार्नी जनरल उस मामले को क्यों लटकाता जा रहा है? ...**(समय की घंटी)**... वह इसे लिंगर ऑन करता जा रहा है, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। ...**(समय की घंटी)**... हम किसी दलित का हिस्सा काटने के लिए नहीं कह रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**... मायावती जी से लेकर, हमारे नेता नीतीश कुमार जी से लेकर, रामविलास पासवान से लेकर, करुणानिधि जी से लेकर सभी पार्टियां ...**(समय की घंटी)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : It will not go on record.

श्री अली अनवर अंसारी : \*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : It will not go on record. No, no. Please, it is over. It is not going on record. It is not going on record. अंसारी जी, बैठ जाइए।

श्री अली अनवर अंसारी : \*

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अंसारी जी, बैठ जाइए। अंसारी जी, बैठिए। अंसारी जी, बैठिए। Take your seat. Take your seat. It is not going on record. What are you doing?

श्री अली अनवर अंसारी : \*

चौधरी मुनब्बर सलीम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है। ...**(व्यवधान)**...

چودھری منیر سالم : اب سبھا ادھیکش مبودے، مددے بھی بولنا بے  
[—] (مدخت) —

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No. I told you it is not going on record. This is indiscipline. अंसारी जी, बैठ जाइए। You take your seat. You take your seat. You sit down, Ansariji. What is this? Ansariji, take your seat. You sit down, Ansariji. What is this? Mr. Munabbar, you listen. You are a new Member. You should read the rule book. I have told you the other day also. If you want to speak, you have to give your name before the discussion starts. The other day I told you that. I have already 10 names before me. And, you are raising your hand! What should I do? Should I not call these ten Members? I have already advised you the other day. Try to read rules and understand something. Hon. Members, I am very clear. We should understand what is what. This is Half-an-Hour discussion. If you want a discussion on the Working of the Ministry of Minority Affairs, the Chair does not have any objection. Give a notice. We will do that. I can sit for hours. But, I have to go by rules. This is Half-an-Hour discussion where a Member can ask questions. Ansariji, in fact, you disobeyed me. I am sorry. He is my friend. He should not have been done like this. So, there are

\* Not recorded.

† Transliteration in Urdu Script.

## [PROF. P.J. KURIEN]

7 Members. I have no problem to call Mr. Munabbar also as 8th Member. But, I am requesting the hon. Members to ask questions. Anything other than questions, I will expunge from the record. I am telling you. You only ask questions. You can ask it in 2 or 3 sentences. I have no problem. But, the rule says that you can only ask questions. Therefore, I will allow Munabbar also. If Members stick to the rules, I can allow more Members. That is the point. So, in 2 or 3 sentence you put your questions. I mean, in two minutes, you put questions. Don't give lectures. Everybody knows the lecture you are making that a particular community is backward. Everybody knows. I also know. Therefore, you put questions. Now, Shri Husain Dalwai. Don't make pleasantries, put questions.

**श्री हुसैन दलवई** (महाराष्ट्र) : सर, मेरा कहना यह है कि सच्चर कमेटी आई, 15 प्वाइंट्स प्रोग्राम्स आए, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे कुछ सवाल हैं, जिन्हें मैं मंत्री जी के सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे इनके ऊपर विचार करेंगे। जैसे आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वह स्कॉलरशिप restricted है। आपको कुछ लोगों को कुछ अमाउंट देना है, आप उनको दीजिए।

आप उसको universal कीजिए। जो-जो गरीब मुसलमान हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसके लिए आप नियम तय कीजिए, ताकि वह सबको मिल सके। सच्चर कमेटी में equal opportunity commission की बात कही गई है, अभी तक वह स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए आप उसको जल्दी से जल्दी स्थापित कीजिए। अगर आप चाहें तो minorities के बजाए, उसको सबके लिए रखना चाहें, तो सबके लिए रखें, लेकिन वह होना बहुत जरूरी है।

मेरी बहुत दिनों से यह मांग है कि जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं, जैसे दलित और आदिवासियों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, वैसे ही रेजिडेंशियल स्कूल इन मुस्लिम बच्चों के लिए भी तैयार कीजिए क्योंकि इसका उनको बहुत फायदा होगा। आज मुसलमानों में एजुकेशन के प्रति एक वातावरण तैयार हुआ है और उसका फायदा उठाना चाहिए। हर बच्चा स्कूल में जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां भी मुस्लिम बस्ती होती है, वहां पर कुछ न कुछ छोटे-मोटे धन्धे होते हैं, जैसे कहीं पर कपड़े का धन्धा होता है, कहीं गलीचे का धन्धा होता है और कहीं पर चमड़े का होता है। वे लोग कुछ न कुछ धन्धा करते रहते हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती है इसलिए वे झोपड़-पट्टी में ही अपना काम-धन्धा करते रहते हैं। क्या सरकार उनके लिए इंडस्ट्रियल हाउस बनाने की बात सोच सकती है। इस बारे में मेरा यह कहना है कि सरकार उनको छोटे-छोटे काम करने की सलाह दे, ताकि उनमें उनका मजदूर भी ठीक तरह से काम कर सके। इस तरह से काम करके वे लोग बड़े पैमाने पर फैरेन एक्सचेंज भी कमाएंगे, क्योंकि उनके सारे काम इस तरह के होते हैं।

दूसरी बात यह है कि Bhiwandi, Malegaon, Dhule, Jalgaon, में टेक्स्टाइल ... (समय की घंटी)... सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : हां, पूछिए-पूछिए।

**श्री हुसैन दलवई** : टेक्स्टाइल इंडस्ट्री की बात आए, तो वह इचलकरंजी में लगाएं, जहां बड़े पैमान पर मुस्लिम हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जहां इसकी आवश्यकता है, वहीं बनाएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास वहां इंडस्ट्री बनाने का इंतजाम है या नहीं, यदि नहीं है तो क्या वहां बनाने की इच्छा है?

मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि माइनॉरिटीज के 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें बड़े-बड़े माइनॉरिटीज़ ब्लॉक्स हैं। मैंने सुना है कि आपने ब्लॉक्स की बात की है, अगर की है तो अच्छी बात है और हमें इस बारे में जानकारी दी जाए। मुस्लिम स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लिए जमीन नहीं दी जाती है, दूसरी कम्युनिटीज के लिए जगह दी जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि इनके लिए जमीन देने के बारे में भी सोचिए। अगर वक्फ की जमीन एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो इस्तेमाल कीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन)** : ओ.के. हो गया, हो गया।

**श्री हुसैन दलवई** : जैसे SC, ST और OBC के लोगों को फायदा मिलता है, ... (समय की घंटी)... वही फायदा मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों को भी मिलना चाहिए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन)** : आपके तीन मिनट हो गए हैं।

**श्री हुसैन दलवई** : आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में हमारे फाजिल दोस्त श्री मुख्तार अब्बास नक़वी साहब ने भी कहा है। उनकी पार्टी हमेशा इसके विरोध में रहती थी, आज वह भी इसके साथ में है। ... (व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन)** : आपके तीन मिनट हो गए हैं।

**श्री हुसैन दलवई** : आप इस पर पूरे जोर से काम कीजिए।

**श्री वी. हनुमंत राव (आन्ध्र प्रदेश)** : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कोई शेर व शायरी नहीं सुनाऊंगा, मैं डॉयरेक्ट अपने विषय पर आ रहा हूं। सर, मेरे बोलने के लिए केवल दो ही इश्यु हैं। आप जितने भी scholarships और entrepreneurship के बारे में बोल रहे हैं, अब तक कितने स्कूल खोले हैं और कितने scholarship दिए हैं, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है? वहां वक्फ प्रॉपटीज भी हैं। आप SEZ के वास्ते हजारों एकड़ जमीन दे रहे हैं, मगर जो गरीब मुसलमान बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल रही है और आप वहां स्कूल नहीं खोल रहे हैं। अगर entrepreneurship में स्पेशली मोटर मैकेनिक, साइकिल मैकेनिक आदि छोटे कामों के लिए ट्रेनिंग देंगे, तो मुस्लिम बरित्यों में रहने वाले बच्चे आगे बढ़ेंगे। आजकल मुसलमानों में भी पढ़ने का बड़ा interest पैदा हो रहा है। बच्चे यहां scholarship में पढ़कर फॉरेन जाना चाहते हैं। मुझे पता है कि एक लड़के के वास्ते मैंने कम से कम 15 बैंकों के चक्कर लगाए हैं, उन्होंने यह कहा कि scholarship देने के लिए यह लैटर लाओ, वह लैटर लाओ, अगर उसके पास जमीन है तो फिर मिल सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के कानून की बातें करते रहते हैं फिर मुस्लिम बच्चे क्या पढ़ेंगे? मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि करीम नगर के कलेक्टर ने अब तक तीन मर्तबा मीटिंग करने की बात की है, लेकिन तीनों ही बार postpone कर दी। क्या ऐसी हालत में सच्चर कमेटी इम्पीलीमेंट हो सकती है? मुस्लिम लोग समझते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है।

वे बार-बार मीटिंग रखते हैं और बार-बार पोस्टपोन कर देते हैं, जिससे एक wrong message जा रहा है। एक तरफ तो सरकार की गरीबों के साथ, माइनॉरिटी के साथ आगे बढ़ने की नीयत ठीक है, लेकिन उस नीयत का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। The Collectors are not taking any interest. ऐसे कलेक्टर लोगों पर कोई ऐक्शन लेना चाहिए। देश भर में जितने कलेक्टर हैं, उनसे सच्चर कमेटी ने कहा है कि मीटिंग बुलाइए। अभी तक तीन मर्तबा मीटिंग बुलाई है और तीन मर्तबा पोस्टपोन की है, इससे क्या मैसेज जाएगा? मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर इसका ध्यान रखें। जिस प्रकार से स्पेशन इवन्मॉमिक जोन है, वैसे ही गरीबों के लिए इंडस्ट्री की व्यवस्था हो। ... (व्यवधान).... दूसरी बात और आखिरी बात वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर है। सर वक्फ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। मुतवल्ली वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और सरकार देखती रह जाती

5.00 P.M.

[श्री वी हनुमंत राव]

है। आप इस पर ध्यान दें कि वक्फ प्रॉपर्टी को बेचना और खरीदना नहीं है। आज बड़े-बड़े सरमाएदार जमीनें लेकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ऐसा होने पर क्या गरीब आदमी को, मुसलमान को गुस्सा नहीं आएगा? आप मुसलमान की बात केवल स्पीच में मत कीजिए, यदि आप ईमानदारी से इसको, वक्फ प्रॉपर्टी को बेचने से रोकेंगे तो मुसलमानों का भला होगा, उनकी पढ़ाई और नौकरियों में भी तब्दीली आएगी। इतनी बात कहकर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha) : Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I have two-three questions on which I would like to seek clarifications from the Minister. You have selected 90 districts to develop the socio-economic conditions of the minorities. In Odisha, we have 30 districts. But, only one district, the smallest district by name Gajapati, is selected for this programme where a number of Christians are living; they are mostly *divasis*. But, in the rest of the 29 districts, there are so many pockets or blocks where Muslims are in more numbers. But, they are not getting the facility because those districts do not have more than 25 per cent of the population. My request is, instead of taking the district as the base, you may please select the blocks where more than 15 per cent of the population belongs to minorities. That way, they would get the benefits and develop.

Secondly, as the topic of discussion itself explains, promotion of entrepreneurship and self-employment among minorities is the main thing. In order to develop the entrepreneurship skills, we need to educate the children of minority communities. So, education is the top, priority. Then, we need to build skills in them. For building the skills, they require ITIS and polytechnics. In Odisha, I have seen that some educated people among minorities want to set up their own ITIS. But, they are not getting enough opportunities; they are not getting loans to establish institutions. If you treat them as minority students, to build up skills in different and specific trades, then they can be useful in the particular regions, in the districts of their States. We need to look into it.

Sir, in regard to self-employment, most of the minority people are poor. They do not have the required capital to invest. So, loans should be given to them on easy terms so that they build their own schools, ITES or training centres. About self-employment, I request the hon. Minister to take specific data from different States as to the percentage of Muslims, Christians and other minorities getting their share of opportunities in employment. If you do not have a comprehensive approach, then the inclusive growth about which you are talking, cannot be achieved; this inclusive growth would be minus minorities, minus SCs, minus STs and minus OBCs. Whose development do you seek then? That is why I have requested you. Please pay attention to the points I have mentioned. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Mr. Rajeeve, put questions only. You have got two minutes.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala) : Sir, what is the final position of the Government to include a sub-plan for minorities on the line of Tribal Plan? Sir, I want to know whether the Government has formulated any specific programme for self-employed or home-based workers to provide skill, credit, technology and market support in backward districts; if so, what is the allocation for that project. Third, how many ITIs and polytechnics and other institutions have been started as per the recommendations of the Sachar Committee? I want to know whether any alternative mechanism has been formulated to identify and charged with the task of providing institutional support, like market linkage, skill upgradation, funding of trades being run by Muslim artisans. Sir, my next question is whether the Small Industrial Development Bank of India, SIDBI, should set aside any dedicated fund for training of minorities, under its Entrepreneur Development Programme; if so, what is the extent of the fund. I want to know whether the Government has given any incentive to start new branches in Muslim-concentrated districts; if so, what is the quantum of the incentive. Next question is whether the Government has formulated any specific scheme to ensure smooth flow of micro credit or priority sector advances; if so, what are the steps taken by them and what is the allocation for this programme.

Sir, I want to know whether the Government has any plan to formulate any policy for enhancing the participation of the minorities in the micro credit schemes of NABARD; if so, what are the schemes; what is the allocation for that; and what is the achievement of it. So, these are my questions to the hon. Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : I think, this is how it should be. If every hon. Member follows Rajeeve, I think, that is correct. That is a correct example; put questions. Now, Shri Tariq Anwar.

**श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र)** : थैंक्यू सर। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यह बात सही कही गई, यहाँ माननीय सदस्यों ने अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के बारे में इस बात की चर्चा की है कि उनकी जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति है, उसे देखते हुए सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनरॉरिटी अफेयर्स ने कार्य किया है। यह कहना उचित नहीं होगा कि कोई काम नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। इसमें मैंने देखा और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 11th Five Year Plan में 7 हजार करोड़ रुपए माइनरॉरिटी कम्युनिटी के विकास के लिए, उनके educational empowerment, area development, economic empowerment, strengthening of minority institutions के लिए दिए गए। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि इसमें खास तौर पर यह बात जाहिर नहीं हुई है, हालांकि स्कॉलरशिप में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय में अलग-अलग कम्युनिटीज़, जिनमें मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी आते हैं, उनको कितनी-कितनी स्कॉलरशिप दी गई। उसी तरह से हम हर क्षेत्र में चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की जो समस्या है, वह दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से

[**श्री तारिक अनवर**]

अलग है। इस बात की चर्चा और लोगों ने भी कि हम उनके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि खास तौर पर और जैसा कि सच्चर कमेटी ने भी यह बात कही थी कि मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अलग से, विशेष रूप से कार्यक्रम चलाने की जरूरत है और ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसे खास तौर पर इंदिरा आवास योजना के बारे में है, बैंक क्रेडिट के बारे में है, इंडस्ट्रियल ड्रेनिंग इस्टिट्यूट के बारे में है या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, ऐसी जितनी भी योजनाएँ सरकार की हैं, उनमें मुस्लिम समुदाय के लिए क्या प्रावधान किया गया है? किस तरह से उसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुँच सकें? हमारे बहुत सारे कार्यक्रम इसलिए भी इम्प्लमेंट नहीं हो पाते हैं कि लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है। उस समुदाय के लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है।

इस तरह, एक तो उनकी इम्प्लमेंटेशन की बात है और साथ-ही-साथ उनकी मॉनिटरिंग की भी बात है। सरकारी की जितनी भी योजनाएँ होती हैं, उनके बारे में यह सवाल अक्सर उठता है कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती। अगर उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत-सारे कार्य आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतना जानना चाहूँगा कि ... (समय की घटी) ... 11th five-year plan में तो आपने 7000 करोड़ का प्रावधान रखा था..

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN)** : Please conclude.

**श्री तारिक अनवर** : अब यह 12th five-year plan चल रहा है, तो उसमें आप उसको कितना बढ़ाने जा रहे हैं और उसको अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग community के हिसाब से उस पर कितना खर्च करेंगे? इसकी जानकारी हम चाहते हैं। उसी तरह से स्कॉलरशिप में भी है। हम यह जानना चाहेंगे कि शिक्षण संस्थान बनाने में और जितनी भी ऐसी सुविधाएँ हैं, जिनके बारे में माइनॉरिटी मंत्रालय ने संकल्प लिया है, उनको पूरा करने की दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं? धन्यवाद।

**श्री राम कृपाल यादव (बिहार)** : सर, हमारा हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है, जिसमें मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है। हम विश्व के दूसरे ऐसे देश हैं, जहाँ इनकी आबादी दूसरे स्थान पर है, 20 करोड़ है। हमसे ज्यादा आबादी, लगभग 22 करोड़ इंडोनेशिया की है और हमसे कम पाकिस्तान की है, मात्र 16 करोड़। इतनी बड़ी आबादी को अगर हम फटेहाली में रखने का काम करेंगे, इसको देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम नहीं करेंगे, इसको नौकरी में जगह नहीं देंगे, इसकी शैक्षणिक स्थिति को ठीक नहीं करेंगे और इसके रहने-खाने की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, तो सर, इतनी बड़ी आबादी को नेपोलेक्ट करके कोई देश खुशहाल कैसे रह सकता है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। यह हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। इतनी बड़ी आबादी को हम भूखे-नगे और फटेहाली में देख रहे हैं और सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, मौन बैठी हुई है।

जब सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दी तब बातें समझ में आईं। आपने यह कमिटमेंट किया कि मैं सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करूँगा। आप इसे लागू करने का प्रयास किस रूप में कर रहे हैं, यह आप बताइए? आपने उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम्स दी हैं। पूरे देश में 90 ऐसे जिले हैं, जहाँ माइनॉरिटीज की आबादी ज्यादा है, उनका आपने चयन किया। सर, मैं बिहार प्रदेश से आता हूँ। बिहार में इनकी बहुत अच्छी-खासी आबादी है। वहाँ 7 जिलों के लिए आपने पैसा आवंटित किया है। यह Multi Sectoral Development Programme जो चल रहा है, इसके तहत आपने पैसा दिया है। सर, अब जो स्थिति है, उसका एक छोटा-सा आंकड़ा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप जो पैसा दे रहे हैं, अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो यही हश होगा। सिर्फ़ पैसा देकर आप क्या कीजिएगा? आपने इसमें कौन-सा मॉनिटरिंग सिस्टम

लगाया है? अगर यह राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया, तो जो राज्य सरकार माइनरिटीज़ के हित में काम करने वाली नहीं है या जिसको माइनरिटी के प्रति विद्वेष है, गुस्सा है, तो वह उनका डेवलपमेंट कहाँ से करेगी, यह आप मुझे बताइए?

आपने जो राशि आवंटित की है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आपने आधी-अधूरी राशि आवंटित की है। उसमें से बंगाल में मात्र 51 परसेंट, उत्तर प्रदेश में 33 परसेंट, बिहार में 31 परसेंट और असम में 20 परसेंट राशि खर्च हुई। अब समझिए कि अगर आपने इतनी ही राशि उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए दी, तो किर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इससे वहाँ के लोगों का उत्थान होगा और आपका जो प्रोग्राम है, वह सफलीभूत हो पाएगा? आपने इसके प्रति कौन-से एक्शन लेने का काम किया है? क्या आप कर रहे हैं और क्या आप राज्यों पर छोड़ देंगे? क्या आप उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे?

सर, अब शिक्षा की स्थिति की बात है। बिहार की शैक्षणिक स्थिति ... (व्यवधान) ... सर, बस में खत्म कर रहा हूँ। सब को तो आप टाइम देते हैं। मेरा भी तो कुभी कुछ ख्याल कीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.के. कुरियन)** : आप क्वेश्चन पूछिए।

**श्री राम कृपाल यादव** : सर, मुझे भी थोड़ा टाइम और दे दीजिए। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। मुझे थोड़ा-सा और टाइम दे दीजिए। ... (व्यवधान) ...

आप उनकी शैक्षणिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं। कल मैंने स्पेशल मेंशन के माध्यम से इसे उठाया था। पूरे देश के पैमाने पर जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, क्या आपने कभी यह देखा है कि वहाँ उर्दू की पढ़ाई भी होती है? जो लोग केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं या सेना में कार्यरत हैं और केन्द्रीय सेवाओं में समय-समय पर स्थानांतरण होता रहता है, तो उनके बच्चों के पास केवल केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है।

1087 केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनमें से एक में भी उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है। आपने कभी इस पर गौर फरमाया है? आप इस इस पर क्या कार्यवाही करेंगे?

आप कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं। ... (समय की घंटी) ...। आज स्थिति यह है कि सेन्ट्रल फोर्स की नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मात्र एक प्रतिशत है। अगर आप इतनी बड़ी आबादी को मुख्य धारा में जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति को समालने का काम नहीं कर रहे हैं ... (व्यवधान) ...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन)** : आपके तीन मिनट हो गए, कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री राम कृपाल यादव** : \*

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KUREIN)** : No, no. It won't go on record.

**श्री राम कृपाल यादव** : सर, कृपया मुझे अपना प्रश्न पूछने दीजिए। ... (व्यवधान) ...

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN)** : Put the question.

**श्री राम कृपाल यादव** : अगर यही स्थिति रही, तो देश का कभी भला होने वाला नहीं है। मुसलमान लोग इस देश के लिए अपना खुन-पसीना बहाते हैं। अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश की रक्षा और मान-सम्मान बनाए रखने का काम करते हैं।

\* Not recorded.

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Please conclude.

**श्री राम कृपाल यादव :** सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में उनकी शैक्षणिक स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या करेंगे? उनको नौकरियों में हक मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे? उनके उत्थान के लिए आपने जो राशि आवंटित की है, उस राशि का खर्च कब तक होगा? आप उनको आगे बढ़ाने के लिए और कौन-से उपाय करने जा रहे हैं? ...**(समय की घंटी)...** सच्चर कमिश्नर की रिपोर्ट में कई तरह की अनुशंसाएं की गई हैं, उन अनुशंसाओं को लागू करने के लिए आप कब तक कार्यवाही करेंगे? जिन राज्यों में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उन राज्यों में पैसा कैसे खर्च होगा और यह कब तक खर्च होगा? बहुत-बहुत धन्यवाद।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Now, Shri Avtar Singh. आप सिर्फ अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री अवतार सिंह करीमपुरी** (उत्तर प्रदेश) : सर, तारांकित प्रश्न संख्या 423 के बारे में आज जो चर्चा हो रही है, वह अल्पसंख्यकों के बीच उद्यमता और स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में है। अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमान के साथ-साथ देश का सिख, क्रिश्चन और बुद्धिस्त भी आते हैं। सर, आजादी के बाद देश में एक सोची-समझी साजिश के तहत पब्लिक सेक्टर में अल्पसंख्यकों के participation को कम किया गया है। 1947 तक पब्लिक सेक्टर में 33 परसेंट मुस्लिम थे। उसके बाद जब से आपके हाथों में उनकी देखभाल का कार्य आया, तो आज वे आपकी कृपा से 3 परसेंट हो गए हैं। इसका क्या कारण है और आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? आपके पास शब्द बड़े अच्छे हैं और कर्म बहुत बुरे हैं। जब तक कर्म अच्छे नहीं होंगे, तब तक अच्छे शब्द कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे।

मान्यवर, 90 जिलों को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र declare किया गया है। पब्लिक सैक्टर के रोजगार में जो अल्पसंख्यकों का representation कम हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको शिक्षा में बड़े पैमाने पर पीछे धकेला गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब से अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा Fifteen-point Multi-Sectoral Programme शुरू किया गया है, तब से उसके तहत इन 90 जिलों में कितने ITI खोले गए हैं और कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए हैं, कितने educational institutions or educational centres create किए गए हैं? आपने किस हद तक मदरसों की शिक्षा को recognize किया है?

इसके अलावा जो 3,700 करोड़ का बजट है, मैं समझता हूँ कि 90 जिलों के लिए यह औसत 41 करोड़ होता है, जो कि जिले की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। इसके बारे में आप प्रयास कीजिए, योजना आयोग के साथ बैठक कीजिए। अगर हम यह consider करते हैं कि 20 परसेंट मुस्लिम हैं और उनके अलावासिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्त हैं, अगर हम ईमानदारी से अल्पसंख्यकों के social and economic स्टेटस को बराबर करना चाहते हैं, उनको equal opportunity देना चाहते हैं, तो यह बजट भी हमें उनकी जनसंख्या के हिसाब review करना चाहिए। ...**(समय की घंटी)...**

सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं क्येश्चन कर रहा हूँ, शेर नहीं सुना रहा हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) :** आप क्येश्चन पूछिए।

**श्री अवतार सिंह करीमपुरी :** मैं क्येश्चन ही पूछ रहा हूँ, मैं बजट को बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। उसके अलावा मंत्री जी, आपकी जो माइनरिटीज की मिनिस्ट्री है, इसके बारे में आप कृपया हमें यह जानकारी जरूर दीजिए कि वहाँ उर्दू की कितनी पोस्ट्स हैं और उनमें से कितनी पोस्ट्स खाली हैं? वे पोस्ट्स कब से खाली

पड़ी हैं और क्यों खाली पड़ी हैं? अगर माइनॉरिटीज की मिनिस्ट्री को उर्दू का टाइपिस्ट नहीं मिल रहा, उर्दू वाला डिप्टी डायरेक्टर नहीं मिल रहा और वह कई सालों से नहीं मिल रहा, तो किर क्या आप माइनॉरिटीज को आगे बढ़ाने का जिम्मा निभा सकेगे? ... (समय की घंटी)...

इसके अलावा, रिजर्वेशन की भी बात है। महोदय, मंत्री जी ने दो-चार महीने पहले बड़े जोर से यह स्टैंड लिया कि हम माइनॉरिटीज को साढ़े चार परसेंट रिजर्वेशन देकर, उनका सदियों से जो शोषण हो रहा है, उससे उनको उबार देंगे, लेकिन इलेक्शन निकल गया और जो यह कह रहे थे, वह मामला भी बन्द हो गया। अब हम यह कहना चाहते हैं कि आप उनको साढ़े चार परसेंट देकर इंसाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बेइंसाफी कर रहे हैं और इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुस्लिम की पॉपुलेशन 20 परसेंट है, उसके अलावा सिक्ख, बुद्धिस्ट्स और क्रिश्चियंस हैं। ... (समय की घंटी) ... सर, घंटी मत बजाइए। एक-आधा मिनट दे दीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन)** : नहीं, अब हो गया।

**श्री अवतार सिंह करीमपुरी** : समय हो गया, यह हमें भी मालूम है, लेकिन इसको भी बहुत समय हो गया, 65 साल हो गये। ... (समय की घंटी) ... हम यह कहते हैं कि आप रिजर्वेशन की 50 परसेंट restriction को तोड़िए। आप शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड में घुसने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप उसके अलावा प्रबंध कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। ... (समय की घंटी) ... आप हिम्मत कीजिए और हिम्मत से आगे बढ़िए, लेकिन साढ़े चार परसेंट से कुछ नहीं होने वाला है। तीन परसेंट तो पहले ही है। ... (व्यवधान) ...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन)** : बस, हो गया। अब आप बैठिए।

**श्री अवतार सिंह करीमपुरी** : बस, अब एक आखिरी सवाल, प्लीज़।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन)** : करीमपुरी जी, देखिए आपने कितने मिनट्स लिए।

**श्री अवतार सिंह करीमपुरी** : सर, अब बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। 1964 में जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी थी, तो हम यह जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी या लैंड है, उसके ऊपर लैंड माफिया ने कितना एनक्रोच कर लिया है और उसको छुड़वाने के लिए सरकार क्या कर रही है? अब हम आपसे यह अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि आजादी के बाद जिस माइनॉरिटी की मस्जिद को, गुरुद्वारे को और चर्च को तोड़ा गया है, उस माइनॉरिटी की जान-माल और ईमान की सुरक्षा के लिए आप ईमानदारी से आगे बढ़ें, तभी वे सोशल और इकानौमिक तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।

**चौधरी मुनब्बर सलीम** : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनसे एक सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बन कर खड़ी है, उत्तर प्रदेश की विधान सभा से बिल पारित है, मुसलमानों को रिजर्वेशन है, उस यूनिवर्सिटी में तीन सौ करोड़ रुपये की इमारतें, जमीन आदि सब हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी वहाँ की एक पब्लिक मीटिंग में यह ऐलान करके आई थीं कि इस यूनिवर्सिटी को हम चलाएँगे, तो उसको आप कब तक शुरू करेंगे?

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछली बार हाउस के अंदर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने सच्चर कमेटी की 40 फीसदी सिफारिशें पूरी कर दी हैं। यहाँ तो उन 40 फीसदी सिफारिशों का पूरा ब्यौरा सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने इसके बारे में लिख कर दरखास्त की थी और आज हाउस में आपके ज़रिये भी यह दरखास्त कर रहा हूँ कि वे बताएँ कि वे कौन-सी 40 फीसदी सिफारिशें हैं, जिनको पूरा किया गया है? इस हाउस का सदस्य होने के नाते मुझे इसकी जानकारी लिखित में भिजवा दें। मैं बस यही कहना चाहता हूँ।

چودھری منیر سلیم (اٹر پر迪ش) : ملقائے اب سبھا ادھیکش جی، ملقائے منقري جي بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اٹر پر迪ش کسے رام پور میں 'جوپر یونیورسٹی' کیے نام سے ایک یونیورسٹی بن کر کھڑی ہے، اٹر پر迪ش کی ودھان سبھا سے بل پارت ہے، مسلمانوں کو رزرو پشن ہے، اس یونیورسٹی میں تین سو کروڑ روپے کی عمارتیں، زمین وغیرہ سب ہیں اور کانگریس کی راشٹریہ ادھیکش سونا جی وہاں کی ایک بیلڈنگ میونگ میں بے اعلان کر کے اُنہیں کہ اس یونیورسٹی کو بم چلانیں گے، تو اس کو کب تک شروع کریں گے؟

دوسرا، میں یہ جانتا چاہتا ہوں کہ بجهائی بل باؤس کے اندر ملقائے منقري جی نے کہا تھا کہ یہ نئے سچر کمپنی کی 40 فیصدی سفارشیں پوری کر دی ہیں۔ یہاں تو ان 40 فیصدو سفارشوں کو پورا بیورا سنالا نہیں جا سکتا، لیکن میں نے اس کے بارے میں لکھ کر درخواست کی تھی اور آج باؤس میں اُب کے ذریعے یہی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بتائیں کہ وہ کون سے 40 فیصدی سفارشیں پوری ہیں، جن کو پورا کیا گیا ہے؟ اس باؤس کا سدمتے یونیس کے ناطے مجھے اس کی جانکاری لکھتا میں بھجوادیں۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں۔

ختم شد

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA (Karnataka) : Since the Chair has authorized me to put two questions, I will put two questions only. One, has an objective evaluation been done, at any time, of the impact which *Madrasa*-type of education has on the competitive spirit of the children and how it takes away the scientific outlook of the children which, at that age, other children get? Has any evaluation been done? Secondly, have you ever considered amendment and changes in marriage laws and curbing the practice of consanguineous marriages, which bring down the physical standards of the children?

When I was in bureaucracy, as the Home Commissioner, I tried to take as many Muslims in police force as possible. But they were not coming up to the physical standards required for that. One of the reasons for that is this. Unfortunately, we do not

---

<sup>†</sup> Transliteration in Urdu Script.

address these basic issues because there is a vested interest in keeping the Muslim minority as a coveted vote bank. I am sorry to say this. Has the Minister addressed these two issues?

**THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED) :** Sir, I am extremely grateful to the hon. Members and I do understand that some Members have other commitments as well.

**श्री मोहम्मद अदीब :** सर, हिन्दी में बोलें।

**श्री सलमान खुर्शीद :** हिन्दी पर भी आऊंगा, उर्दू पर भी आऊंगा, सभी जुबानों में बोलेंगे। कुछ लोग अंग्रेजी में बोले, इसलिए पहले अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूं।

मान्यवर, मैं सबसे पहले तो सारे सदस्यगणों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और सुझाव भी दिए। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि हरेक अपने-अपने तजुर्बे और अनुभव को सामने रखकर, हरेक ने प्रयास किया है कि देश के एक संजीदा और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकें। यह थोड़ा-सा हमारा दुर्भाग्य रहा, कुछ हमारे सदस्यगण का यह दुर्भाग्य रहा कि जो नियमाली है और जिस नियम के तहत आज यह चर्चा हो रही है, वह बड़ी सीमित हो गई है। मैं मोहम्मद अदीब साहब का खास तौर पर आभारी हूं कि उन्होंने इस चर्चा को बढ़ाने का एक प्रयास किया है। मुझे थोड़ा सा खेद हुआ, दुःख हुआ कि जो हमारे पास दस्तावेज और सूचियां थीं, जो हमारे पास तथ्य थे, जो हमारे पास फैक्ट्स थे, हमने यह चाहा कि इस महत्वपूर्ण चर्चा से पहले कुछ सदस्यगण प्राप्त कर लें, ताकि उनके प्रकाश और रोशनी में और उनकी जानकारी में हम इस चर्चा को और गम्भीरता से आगे बढ़ा सकें। मैं समझता हूं कि सदस्यगण चाहेंगे कि यह सारी सूचना, ये सारे तथ्य हम उनको प्रस्तुत करें और यह हमने पहले ही फैसला किया है कि आप सभी माननीय साथियों को ये सारी सूचनाएं प्रस्तुत करेंगे, जो आज नहीं तो आगे की भी चर्चा में आपके लिए यह काम आएगा। आपका और हमारा इस देश का बहुत-सा सरमाया, सूचना का सरमाया हमारी वेबसाइट पर है। लेकिन शायद हम लोगों को इतना अलग से अलग नहीं मिल पाता कि वेबसाइट पर बैठकर विस्तार से ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट्स निकाल सकें। इसलिए हम उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रस्तुत करेंगे और समय-समय पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे वह हम और भी आपको प्रस्तुत करेंगे।

मान्यवर, यहां आज बहुत सारे सवाल आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तथा सदस्यगणों की भी आज्ञा हो तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको मिलना चाहिए और जिनको आज अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो बहुत जल्द उनकी समीक्षा करके जवाब आपको प्रस्तुत कर देंगे।

इतना मैं जरूर कहूँगा कि मुख्तार अब्बास नक़वी साहब ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, मुझे भी एक शेर याद आ गया।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Mr. Minister, what you can do is that you can reply whatever is possible today. Rest of the points you can reply in writing.

**SHRI SALMAN KHURSHEED :** Yes, Sir, I will do that. I will reply to the rest of the points later. मैं एक शेर प्रस्तुत कर देता हूँ, जो आपके अंदाज से मेरे दिल में उभर कर आया।

## [SHRI SALMAN KHURSHEED]

“क्यों न इस सादगी पर मर जाएं ए खुदा,  
कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।”

बात यह भी कुछ थी। मैं कहना तो यह चाहता था कि :

“या रब न वो समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात,  
दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और।”

अब उस जुबां से मैं कम से कम आपसे यह कह सकूं कि हमें आज खुशी है और सारे सदस्यगण यहां बड़े प्रसन्न हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर संवेदनशल बात तो कही,.....। आपने ने जो भी कहा हो, लेकिन अंत में आपने गंगा, यमुना को बांटने की बात फिर कर दी। हम चाहेंगे कि आप उनका संगम बनाकर रखें।

**श्री मुख्जार अब्बास नक़वी :** उपसभाध्यक्ष महोदय, हम कभी भी बांटने के पक्ष में नहीं हैं, हम तो देश को जोड़ने के पक्ष में हैं। मैं इसी पर एक बात और कहना चाहता हूं कि,

“अपनी बातों में वो लफ्जों का हुनर रखते हैं,  
खुशियों में भी डुबोने का हुनर रखते हैं।  
झूठ शाहों के सही, फिर भी पकड़ जाते हैं,  
सच किसी का भी हो, बहरहाल असर रखते हैं।”

**श्री सलमान खुर्शीद :** मैं इस चर्चा को मुशायरे में तब्दील नहीं करना चाहता, लेकिन जवाब मेरे पास है,

“आह को चाहिए, एक उम्र असर होने तक,  
कौन जीता है, तेरी जुल्फ़ के सर होने तक।”

मान्यवर, चूंकि यह एक गंभीर विषय है, अगर आपकी इजाजत हो, तो मैं आगे बढ़ूँ? हमारे माननीय सदस्य अली अनवर अंसारी साहब ने Equal Opportunity Commission की बात रखी कि हमने इस कमीशन को आज तक लागू क्यों नहीं किया? वह चले गए। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूँ कि 76 सिफारिशों हमको सच्चर कमेटी से मिली थीं। उन 76 सिफारिशों में से हमने 72 सिफारिशों मार्नी। प्रश्न यह किया गया कि कौन-सी आपने नहीं मारी? हमने सेंसर वाली एक बात को defer किया था, नहीं माना था, लेकिन आप लोगों के साथ चर्चा के बाद अब caste का census हो रहा है जिस पर लोगों का अलग-अलग point of view था, जिसके आंकड़े हमें एक वर्ष के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद उन आंकड़ों की रोशनी में शायद हमारे निर्णय और अच्छे हो सकेंगे, लेकिन Equal Opportunity Commission पर सरकार अभी यह फैसला नहीं कर पायी है और सब की सहमति नहीं बन पायी है कि अगर Equal Opportunity Commission के विचार को यदि सच्चर कमेटी ने ही पैदा किया था, तो वह विचार, वह idea मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है? यह माइनॉरिटीज के लिए क्यों नहीं है? यह सब के लिए क्यों है? Equality Opportunity Commission को सच्चर कमेटी ने सब के लिए कहा था कि जो भी पिछड़े वर्ग या समाज के लोग हैं, चाहे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक हों, उनको समाज में बराबर का अवसर मिल सके और पहले जो आरक्षण की व्यवस्था हमारे सविधान की रही है, उस व्यवस्था से आगे बढ़कर हम affirmative action के तहत सब को equal opportunity देने का एक नया प्रावधान लाएं। इस पर आम सहमति बनेगी तो सरकार इसे सदन के सामने अवश्य लाएंगी, लेकिन इस बारे में अभी सरकार भी चर्चा कर रही है और वह समय-समय पर आप लोगों से भी चर्चा करती है। यह सही है कि आरक्षण के संदर्भ में यह कहा गया कि अर्टिकल 341 के मामले में अभी

तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है। हमने यह निर्णय किया था कि हम यह बात सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य प्रस्तुत कर के सुप्रीम कोर्ट से यह सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में हमारे समाज में और आपस में बहुत बंटवारा है। हमको सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मार्गदर्शन दे दे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जरिस की एक पीठ में दर्ज है और उम्मीद है कि जैसी ही वह पीठ फिर बैठेगी, उनको समय मिलेगा, तो वह अवश्य इसे सुनने के बाद अपना निर्णय देगी।

मान्यवर, आरक्षण में चार, साढ़े चार प्रतिशत के बारे में लोगों के अलग-अलग विचार हैं, इसे मैं स्पष्ट कर दूँ। हम नहीं कहते कि साढ़े 4 प्रतिशत आरक्षण में हम यह मान लें कि हमने आसमान से सितारे तोड़कर किसी की गोद में डाल दिए हैं। हमने सिर्फ वही किया, जोकि सच्चर कमेटी का इशारा था और श्री रंगनाथ मिश्रा ने हमसे कहा था। मान्यवर, श्री रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि कुछ ऐसे अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता है या माना जाना चाहिए। उनको पिछड़ों की सूची में रखना चाहिए, वे हैं और मंडल कमीशन के समय से हैं। उनको अलग से **most backward** मानकर, अलग से हिस्सा मिलना चाहिए।

इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने अल्पसंख्यक बैकवर्ड्स को 4.5 प्रतिशत तक अलग आरक्षण की व्यवस्था बनाने की बात की, जो इन्दिरा साहनी केस की बुनियाद पर है। हमने वह न इलेक्शन के लिए किया था, न वह लॉलीपॉप था, इन्दिरा साहनी केस के जो परामर्श हमें प्राप्त हुए थे, जो सच्चर कमेटी का इशारा था, रंगनाथ मिश्रा का परामर्श था, उसको लेकर हम आगे बढ़े थे। यह 4.5 प्रतिशत क्यों? इसलिए कि रंगनाथ मिश्रा ने यह कहा कि 8.44 परसेंट माइनोरिटीज की बैकवर्ड पापुलेशन है, सही या गलत वह तो जब सेन्सस हमको मिलेगा, हमें स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन रंगनाथ मिश्रा ने कहा था कि 8.44 परसेंट माइनोरिटीज की बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उसका आधा अगर लें तो वह 4.22 होता है, राउण्ड-अप करके उसको हमने 4.5 रखा है। इसमें अगर कोई कमी या कोई त्रुटि रह गई होगी तो जब यह बैकवर्ड की सेन्सस हमारे सामने आएगी, उसमें बात स्पष्ट हो जाएगी। यह अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, यह बैकवर्ड्स में से ही एक हिस्सा कुछ बैकवर्ड्स को दिया गया है, जिसके लिए रंगनाथ मिश्रा ने कहा था और इन्दिरा साहनी का जो केस था उसमें ऐसा आया था। जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड्स हैं, उनमें कौन-कौन हैं? यह भी स्पष्ट कर दूँ, हमारी माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की बैकवर्ड्स की सूची मानते हैं, उसमें सिर्फ पांच समुदाय आते हैं।

महोदय, मैं जानता हूँ कि यहां अदीब साहब ने कहा कि जैनियों को ही सारे पैसे दे दिए गए। दिल्ली में जैन समाज के साथी अल्पसंख्यक माने जाते हैं, मगर हमारे जो केन्द्र की लिस्ट है उसमें जैन समाज के साथी अल्पसंख्यक नहीं माने जाते और वे इसलिए नहीं माने जाते, क्योंकि बाल पाटिल के केस में 11 जजेज का जो एक फैसला था, उसमें यह कह दिया गया था कि अब आप अल्पसंख्यक जिसको भी घोषित करेंगे वह स्टेट की बुनियाद पर करेंगे, चाहे वह लैंचेज के रूप में अल्पसंख्यक हो, चाहे वह रिलीजियन के बेस पर अल्पसंख्यक हो, आप नेशनल कोई माइनोरिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और 11 जजेज का फैसला है। इस 11 जजेज के फैसले को 3 जज,, 4 जज, 5 जज बदल नहीं सकते। जब यह मामला 11 जजेज के सामने या 11 से ज्यादा जजेज के सामने जाएगा, तब इसे तय कर सकते हैं। मेरे मित्र और साथी वहां बैठे हैं, प्रदीप जैन साहब, यह तकरीबन हर हफ्ते मुझसे कहते हैं कि अगर आपकी सूची में और अल्पसंख्यक हैं, तो हम क्यों नहीं, जैन समाज के लोग क्यों नहीं? अलग-अलग प्रांतों ने, कम से कम आठ ऐसे प्रांत हैं, जिन्होंने जैन समाज के लोगों को इस सूची में रखा है। इनको प्राप्त में रखा गया है, केन्द्र में रखने की अभी हमें आज्ञा प्राप्त नहीं है। केन्द्र में तब आएंगे, जब हमें आज्ञा प्राप्त होगी, तब भी यह देखना होगा कि इनका पिछड़ापन है तो कितना है और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमको क्या करना है?

[श्री सलमान खुर्शीद]

जो स्कॉलरशिप्स आज हम बांट रहे हैं, उस पर अदीब साहब ने पूछा कि आपने 1 करोड़ 40 लाख की जो बात की है, क्या आप वह कुछ ही बच्चों को बार-बार देकर उसको 1 करोड़ 40 लाख बता देते हैं? मैं आपके सामने सारे तथ्य करुंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ कि इन स्कॉलरशिप्स के मामले में अलग-अलग हम जितना पूरा पैसा स्कॉलरशिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और उपयोग में लाते हैं उसमें हर वर्ष हर प्रांत के लिए आबादी के हिसाब से और हर प्रांत में अल्पसंख्यक आबादी और विभिन्न अल्पसंख्यकों की आबादी के हिसाब से हम एलोकेशन करते हैं और उसमें फ्रेश और रिन्यूअल्स का अलग-अलग एलोकेशन करते हैं। नई स्कॉलरशिप्स कितनी होंगी, उसका हम अलग से एलोकेशन करते हैं, जैसे कि इस वर्ष में हमने 55,000 का टारगेट बनाया था, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें से 19,505 फ्रेश स्कॉलरशिप्स थी, और 22,929 रिन्यूअल्स थीं, तो रिन्यूअल्स भी होती हैं। यह स्कॉलरशिप्स तीन साल चली हैं और यह स्कॉलरशिप्स डेढ़ करोड़ पर पहुँची हैं। यहां यह बात भी कही गई कि आप इन स्कॉलरशिप्स को डिमांड ब्रेक्स कर दीजिए, युनिवर्सलाइज कर दीजिए, इस पर कोई सीमा मत रखिए। हमने ट्रेवलथ प्लान में प्लानिंग कमीशन के यह सामने प्रस्ताव रखा है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स से बढ़कर कोई और अच्छी चीज नहीं हो सकती।

जहां तक स्कॉलरशिप्स की बात है, मैं इतना बता दूँ कि पिछले साल हमने मुस्लिम समुदाय के लिए जो *fresh scholarships* रखीं, वे 100 फीसदी उनको मिली, इसी तरह इसाई समुदाय के लिए जो *fresh scholarships* रखीं, वे 100 फीसदी उनको मिलीं, सिख समुदाय के लिए जो रखीं, उसमें से उन्होंने सिर्फ 41.07 परसेंट लीं और पारसी समाज के लोगों ने पूरी 100 प्रतिशत लीं।

उपसभाध्यक्ष जी, हमें सबको बराबर देना होता है, चाहे वे अपनी स्कॉलरशिप्स लें या न लें। प्रयास यह होता है कि वे स्कॉलरशिप्स उनको हिसाब से मिलें, ताकि कोई यह न कह सके कि एक समुदाय को स्कॉलरशिप मिली, लेकिन दूसरे समुदाय को स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब *Means-cum-Merit Scholarship* को हमने *online* कर दिया है। आने वाले वर्षों में सारी स्कॉलरशिप्स *online* हो जाएंगी। बच्चे *online* जाकर स्कॉलरशिप्स के लिए *apply* कर सकते हैं और चैक सीधे उनके बैंक एकाउंट में पहुँच जाएंगा। *UID* नम्बर के बाद इसमें और भी सुविधा जो जाएंगी। स्कॉलरशिप में कहीं भी कोई समस्या नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, अगर समस्या कहीं आती है, तो *loans* में आती है। अक्सर आप लोगों को ऐसा लगता है और खेद भी व्यक्त किया गया है कि हम कितना लोन दे पा रहे हैं। हम तो *priority sector loans* दे रहे हैं, उनको लेकर एक प्रश्न उठता है कि ये किसको मिल रहे हैं? जो काम आपने MCDs में किया है, जो 3,000 करोड़ रुपया, साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वह किसको जा रहा है? MCDs में 90 प्रतिशत आबादी मुस्लिम समुदाय की है। जब हम MCDs में पैसा खर्च करते हैं, तो वहां वे उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। हां, अगर सड़क बन रही है, तो सड़क बनाकर हम यह नहीं कह सकते कि इस पर सिर्फ मुसलमान या इसाई चलेंगे। सड़क पर हर हिंदुस्तानी चलेगा और सड़क वहां बनेगी, जहां मुसलमान, इसाई, Zoroastrian, Buddhists ज्यादा रहते हैं, सिख ज्यादा रहते हैं, वहां पर सड़क अवश्य बनेगी। हमारी ओर से सड़क वहां नहीं बनेगी, जहां पर इन लोगों की आबादी कम है, लेकिन हम यह मानकर चलें कि सिर्फ हम ही इनके लिए सड़क नहीं बनाएंगे, दूसरे लोग भी इनके लिए सड़क बनाएंगे, हमारा दूसरा मंत्रालय भी इनके लिए सड़क बनाएगा। इसलिए 11 ऐसे मंत्रालय हैं, जिनके लिए हम *targeting* कर देते हैं कि उनके मंत्रालय से कम से 15 प्रतिशत फायदा अल्पसंख्यकों को जाना चाहिए। वे फिर्स्त हमारे पास हैं और मैं समझता हूँ कि हमने 90 परसेंट ऐसे *targets fix* किए हैं, जहां 15 परसेंट वाला *target* हम हर साल पूरा करते हैं। हर क्वार्टर में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इन *targets* की समीक्षा करती है और उसके बाद ये सेक्रेटरीज की कमेटी में जाते हैं और फिर दोबारा ये सारे लक्ष्य जो पूरे नहीं हो पाए, ये कैबिनेट

के सामने रखे जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम यह सब सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे हैं, क्या हम यह सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, क्या हम यह सिर्फ ईसाइयों और सिख बिरादरी के लोगों के लिए कर रहे हैं? हमारा जवाब है कि हम पूरे समाज के लिए यह करना चाहते हैं और हम पूरे समाज को इकट्ठा और एकत्र करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई पीछे रह जाता है। जो पीछे रह जाता है, उसका हाथ थामना पड़ता है। हाथ किस-किस का थामना है, कैसे थामना है, कहां थामना है, यह सब कानून और हमारा कांस्टीट्यूशन हमें बताता है। कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि आपने बहुत देर तक हाथ थाम लिया, कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि आपने हाथ थामा ही नहीं, कभी-कभी आप कहते हैं कि आप गोद में बिठा रहे हैं, कभी-कभी आप कहते हैं कि आप कंधे पर लाद रहे हैं, कभी-कभी आप कहते हैं कि आपने पीछे छोड़ दिया। तो समय-समय पर इसकी समीक्षा होगी और हमें समय-समय पर correctives लगाने होंगे कि हमने जो लक्ष्य बनाया था, हमने उसको achieve कर लिया है या हमें उसको लेकर आगे बढ़ना है? मैं आपसे यह विनीती करता हूं कि यह सेहरा बांधने की बात नहीं है, यह किसी को दूल्हा बनाने की बात नहीं है। अब चुनाव नहीं है, हमें यहां सिर्फ यह तय करना है कि कभी आप और अभी हम, इस देश के मुखिया बनकर इस देश को चलाएंगे।

और इस देश को चलाने के लिए, यह देश कैसा हो, कितना उज्ज्वल हो, इस देश में लोग कितने सुखी हों, जो हमारे बीच की दरारें हैं, वे कैसे समाप्त हों, ऊंच-नीच की जो दूरी है, वह कैसे समाप्त हो? तो हरेक को ऐसा अवसर मिले कि हर व्यक्ति यह कह सके कि हां, हम खुशहाल हैं, हम अपने देश के लिए योगदान भी देते हैं, हम देश की सेवा भी करते हैं और देश हमारी देख-रेख और देखभाल भी करता है।

महोदय, मैं मानता हूं कि जब लोकतंत्र में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच कभी ऐसा लगता है कि बहुसंख्यकों ने बहुत ज्यादा ले लिया, तो अल्पसंख्यकों की शिकायत आती है। कभी बहुसंख्यकों को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो उनकी भी शिकायत आती है। यह हम संवाद से दूर कर सकते हैं। एक-दूसरे पर कोई आरोप लगाकर या अंगुली उठाकर हम इसे दूर नहीं कर सकते हैं, न हम हम कर पाएंगे, इसलिए हम सब संवाद से इस समस्या का निराकरण करें। समस्या का निराकरण करना है क्योंकि हम सब संविधान से जुड़े हैं। यह काग्रेस पार्टी या यू.पी.ए. का कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे संविधान का कार्यक्रम है। हमारा संविधान यह कहता है कि इस देश के कुचले, पिछड़े और शोषित वर्ग के जो भी लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है। कुछ को संविधान ने identify किया, कुछ को संविधान ने व्यवस्था बनाकर दी। कहीं पर संविधान ने यह कहा कि समय-समय पर सरकार और पार्लियामेंट इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है और इस व्यवस्था में जिसको जोड़ना है, उसको जोड़ ले, जिसको घटाना है, उसको घटा ले, लेकिन समय-समय पर यह फैसला उसने हम पर छोड़ा है और हमें जो समझ आता है, हमारे जो अनुभव हैं और जो आदेश हमें जनता से प्राप्त होते हैं, आप और हम मिलकर उनको आगे लेकर चलते हैं। विवाद होते हैं, तो हम विवादों का समाधान यहां निकलने का प्रयास करते हैं। समाधान निकलते भी हैं और खुशी की बात यह है कि समाधान निकलेंगे।

महोदय, हमारे बी.जे.डी. के उड़ीसा के सदस्य ने कहा कि सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट को हम कैसे लेते हैं? डिस्ट्रिक्ट को हम लेते हैं पच्चीस ... (व्यवधान)...

**श्री तारिक अनवर :** एक सुझाव आया था कि यूनिट को डिस्ट्रिक्ट के बजाय...

**श्री सलमान खुर्शीद :** मैं बता रहा हूं। तो जो स्कीम है, उसमें जहां अल्पसंख्यकों की पच्चीस प्रतिशत आबादी है, वहां हमने डिस्ट्रिक्ट को लिया और अगर बीस प्रतिशत है, लेकिन पांच लाख की आबादी है, तो उसको भी हम सम्मिलित करते हैं और ऐसे 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं समझता हूं कि उनमें ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स वे हैं, जो मुसलमानों के हैं। 66 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, लेकिन यह माना गया है और

[श्री सलमान खुर्शीद]

लोगों का अनुभव यह रहा है कि आपने डिस्ट्रिक्ट का चयन तो कर लिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां अल्पसंख्यक रहते हैं, वहां अगर आप ज्यादा फोकस करें और concentrate करें, तो बेहतर होगा। प्रयास यही होता है ओर हम चाहते हैं कि स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने या जो भी हम MsDP में दें, वह उसी क्षेत्र में जाए, लेकिन कभी उस क्षेत्र में भूमि नहीं मिल पाती, कभी उस क्षेत्र में कोई और समर्था होती है। यह भी संभव है कि प्रान्त की सरकार पूरी तरह से अपना सहयोग न दे, इसलिए अब 12th Plan के लिए हमने प्लानिंग कमिशन को एक सुझाव दिया है। एक सुझाव तो यह है कि आबादी 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दें, क्योंकि अल्पसंख्यकों के मामले में हर जगह 15 प्रतिशत ही माना गया है और स्टैंडिंग कमेटी ने भी हमें यह परामर्श दिया है। अब यह संभव होगा या नहीं होगा, यह तो जब प्लानिंग कमीशन का फैसला आएगा और आपके सारे नेतागण वहां रहेंगे, तभी हमें यह पता चल पाएगा, लेकिन दूसरा प्रस्ताव यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट को न लेकर हम ब्लॉक को ले लें और ब्लॉक को लेने में यह संभव है कि आज जो uncovered districts हैं, उनके कुछ ब्लॉकों में हम पहुंच जाएंगे और हमारे वे ब्लॉक अवश्य कवर हो जाएंगे।

एक बात यह उठी कि आप इसकी निगरानी कैसे करते हैं, इसकी monitoring कैसे करते हैं? मैं मानता हूं और हमारे नक्वी भाई ने यह भी कहा कि monitoring करने के लिए कमेटी की बैठक नहीं होती। अभी हनुमंत राव जी ने यह कहा कि हमको तीन बार कलेक्टर ने कहा कि monitoring की बैठक करेंगे, लेकिन नहीं की। जब मैं मंत्री बना था, उस समय MPs और MLAs का इसमें कोई रोल ही नहीं था। हमने MPs और MLAs को इसमें involve किया। MPs को उनके अपने क्षेत्र और राज्य सभा के MPs को उनके प्रान्त के किसी क्षेत्र की निगरानी में हमने समिलित किया, लेकिन मैं समझता हूं कि उचित यह होगा कि जिस तरह से और निगरानी समितियां हमारी व्यवस्था में हैं, वैसे Fifteen Point Programme की निगरानी समिति की अध्यक्षता भी MP करे, तो बेहतर होगा।

यह प्रस्ताव भी हमने प्लानिंग कमीशन के सामने अगली स्कीम के लिए रखा है, लेकिन National Level Monitors, वे लोग जो पदमुक्त हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनको trained करके ... (व्यवधान)....

**SHRI P. RAJEEVE :** Is there any time-frame for convening the meeting of the Monitoring Committee?

**SHRI SALMAN KHURSHEED :** There is no specific time-frame. We expect that in every three months the meeting should be held. Wherever there is an MCD, Minority Concentrated District, the plan that we have to pay money for, has to come from that Committee. और अगर कमेटी की बैठक नहीं होती है तो फिर वह प्लान हमारे पास नहीं आएगा। फिर प्रश्न यह उठाया जाता है that Rs.3,000 crores were given by you, but you have released only Rs. 2,000 crores. But we can't release the money to a State or a district that is not sending us the plan which can be approved.

**SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala) :** Our experience, in Kerala, is that the Committees were constituted one year ago. But no meeting was held. Not a single meeting was held in Kerala. We are all supposed to be members of the Committee in two or three districts.

**SHRI SALMAN KHURSHEED :** I have a little difficulty there. I urge and write and I even go and request the Chief Ministers. I write and urge. But I have no option today to say that if you don't hold the meeting, I will stop the money. I have no option to say that if you don't hold the meeting, I will come and hold the meeting. We have to have some sense of cooperation between the Centre and the State. I do believe that this is important for the State as well. But, sometimes, they are overtaken by other issues or more urgent and pressing things. But I will request all the hon. Members here, please use everything at your command to persuade your State and your Government to ensure that, both at the State level and at the Central level, these issues are resolved and that the meeting takes place regularly not only to monitor but also to propose some useful things to us. There are many other proposals that have been made here. One proposal is about the Central Forces which Ram Kripalji made. He has also made a proposal about the Kendriya Vidyalayas. As soon as I send you the details you will see कि हर मंत्रालय में, हर कार्यक्रम में प्रयास यह किया जाता है कि inclusion हो, सब लोगों को समिलित किया जाए, उसमें किसी को बाहर न रखा जाए, लेकिन ज्यादा ध्यान माइनरिटीज को दें, यह मानकर कि वे ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं और उनको हमें साथ लाना है। Let me say this to you that, unfortunately, in the scheme of things, in Kerala, every district is above the national average in terms of development. What we do is we give only to those districts that have 25 per cent population, but are below the national level on those main indices that we have created. So, Kerala, unfortunately, does not get the benefit of MCD. So, in the revised plan, possibly, States like Rajasthan where the population is low and States like Kerala where the population is high, but the development index is also high, maybe, we will be able to find some *via media* in which at least some of these programmes...

**SHRI P. RAJEEVE :** We are the victim of development, Sir.

**SHRI SALMAN KHURSHEED :** You are the victim of your good fortune to be what you are. Everyone wants to learn from you. If the whole country becomes like Kerala, then we will not need programmes like this. Then we can do some other programmes. ...*(Interruptions)*... एक बात यह कही गयी कि बजट बहुत कम है। ...*(व्यवधान)*...

**श्री राम कृपाल यादव :** सर, मैंने एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है, पोस्ट की कमी है ...*(व्यवधान)*...

**श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) :** आप इसका टाइम बढ़ा दीजिए क्योंकि 6 बजने में पांच मिनट रह गए हैं। ...*(व्यवधान)*...

**श्री राम कृपाल यादव :** बिहार में जो पैसा आपने दिया है, वह खर्च नहीं हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया आप उसको देखिए। ...*(व्यवधान)*...

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** No more questions. ...*(Interruptions)*...

**श्री सलमान खुर्शीद :** सर, मैं सिर्फ एक बात कह दूँ। ...*(व्यवधान)*...

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Ram Kripalji, you have put your questions. Additional questions can be written to the Minister, not now. You write to the Minister.

**श्री मुख्यार अब्बास नक्वी :** सर, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सभी सदस्यों के प्रश्नों जवाब दिया है। चूंकि अभी इतना समय नहीं है, कुछ जवाब ऐसे होंगे, जिनका जवाब माननीय मंत्री जी अभी नहीं दे सकते इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि मंत्री जी इस बारे में लिखित रूप से विस्तार में सबको सूचना दे दें।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Let him complete. Are you yielding?

**श्री हुसैन दलवई :** मंत्री महोदय, मैंने एक सवाल उठाया था। जो गरीब मुस्लिम हैं, उनके लिए आश्रम की तरह कम से कम हर जिले में एक-एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के बारे में मैंने कहा था। मेरा अनुरोध है कि आप कृपया ऐसा करिए।

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Are you yielding to Mr. Adeeb?

**श्री सलमान खुर्शीद :** सर, मैंने माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो अच्छे सुझाव हैं, उन पर हम विचार करेंगे। अगर हम उनको अपने प्रोग्राम्स में इन्क्लूड कर सकते हैं, तो करेंगे। जो प्रश्न हैं, हम उनके जवाब देंगे। लेकिन अंत में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र नक्वी साहब ने यह कहा था कि जब प्रश्न उठा था, तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पाये और अब तो मंत्री जी ने जवाब दे दिया।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो पी.जे. कुरियन) :** अब तो विस्तार से जवाब दे दिया।

**श्री राम कृपाल यादव :** सर, मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*...

**श्री मोहम्मद अदीब :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन क्लोरिफिकेशन्स पूछना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*...

**جناب محمد ادیب :** اب سہا ادھیکٹس میوڈے، میون دوختن کلیر فکٹریشن پروجئن جاپان بور [—]۔

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** Are you yielding to Shri Adeeb?

**श्री राम कृपाल यादव :** सर, मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*...

**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) :** He is the initiator, so I am allowing him.

**श्री मोहम्मद अदीब :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति के बाद कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने तीन सवाल पूछे थे। जो 13 मंत्रालय आपसे गवर्नर होते हैं, आपकी मिनिस्ट्री उनकी नोडल मिनिस्ट्री है,

---

† Transliteration in Urdu Script.

میسال کے توار پر گاریوں کو کوچ مکان میلتا ہے، آنگنباڑی کی سکیمس ہے، دوسری جیتنی سکیمس ہے، جو 15 سوئیٹ کارکرم کے تھت برتی کا مسلا ہے، انکی کیا دیٹل آپ بائیکرکٹ کرکے ہاؤس کو دے گی کیا کیتھے لے لوگ کہاں سے آئے؟ کیتھے پرسنٹ لون کہاں پر دیا گی؟

+[جنب محمد ادیب]: اب سہا ادھیکش مبودے، میں آپ کی اجازت کے بعد کوئی بحث نہیں کروں گا  
جنباں میں نے تین سوال پوچھے تھے۔ جو 13 منزليہ آپ سے گورنمنٹ پوچھے ہیں، آپ کی  
منزليہ ان کی توکل منزليہ ہے، مذکور کے طور پر غربیوں کو کچھ مکان ملتے ہیں، انگریز  
واڑی کی اسکیس ہیں، دوسری جتنی اسکیس ہیں، جو 15 نکتی پروگرام کے تحت بھرپوری کا  
مسلسل ہے، ان کی کیا تھیں آپ bifurcate کر کے بوس کو نہیں کیے کہ کتنے لوگ کیاں انسے؟  
کتنے طبعہ میں کہاں پر بیا گیا؟]

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is all. You just put your question.

شی ہمداد ادیب: سر، میرے کوئی سوال کیا ہے، میرا پرشن ہے کہ کیا آپ  
ماؤنٹینری کی اسٹینکٹ ہمیشہ بناتے کے سوچے ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جتنے  
میں مسلا ہے اور مسلمانوں کے ڈائریکٹ اسکول 50-100 سال سے exist کر رہے ہیں، کیا  
آپ ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ دے کر ٹریننگ کا پریمیوم کریں گے؟ اگر آپ ان کو ڈائریکٹ  
فونڈنگ دیں، جیسے افریدیش نور پبلر کے پر صلح میں اسلامیہ اسکول کھلائے ہوئے ہیں،  
وہ سسک رہے ہیں، اگر آپ ان کو فنڈنگ کر کے تحریک کالج، لاہ کالج، الجیت ریکٹ کالج میں  
تبدیل کریں، تو ان سے مسلمانوں کے مسئلہ حل ہوں گے اور کرشمن و ملتبر فیز کو ان  
سے فائدہ ہوگا۔

† Transliteration in Urdu Script.

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : हो गया।

श्री मोहम्मद अदीब : सर, जवाब नहीं आया।

[جذبِ محمد ادیب : سر، جواب نہیں آیا۔]

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No, no. No more questions. No, you are not allowed. I have allowed him because he was the initiator. You are not allowed to speak. आप बैठ जाइए।

श्री सलमान खुर्शीद : सर, मैं माननीय सदस्य को जवाब दे देता हूं कि वक्फ का जो मामला है, उसकी सलेक्ट कमेटी से ... (व्यवधान)...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड) : सर, माननीय मंत्री जी ने ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No, please. You did not speak. You are not allowed.

श्री सलमान खुर्शीद : सर, जो वक्फ का मामला है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आ गई है। बहुत जल्द आपके सामने, हाउस के सामने वक्फ का बिल आयेगा और उसमें जो इनकी चिंता है, उस चिंता का हम लोगों ने कुछ निराकरण निकाला है। ... (व्यवधान) ... जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उनके एक-एक बिंदु का विस्तार से जवाब भी देंगा और अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम यू हीं साथ देने का वायदा करो और मैं यू ही नगर्में सुनाता रहूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : The House is adjourned to meet tomorrow at 11 a.m.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 17th May, 2012.

† Transliteration in Urdu Script.